सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-31 अंक-08 22 अप्रैल, 2016 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

अमेरिकी विमानों व युद्धपोतों को ठहरने व ईंधन भरने के लिए भारतीय सैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने देने के फैसले का एसयूसीआई(सी) ने किया कड़ा विरोध

13 अप्रैल 2016 को एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया :

अमेरिकी विमानों व युद्धपोतों को खड़ा करने व ईंधन भरने, मरम्मत व अन्य लॉजिस्टिक उद्देश्यों के लिए भारतीय सैनिक अड्डों पर उतरने देने के भारत सरकार के फैसले का हम कड़ा विरोध करते हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादी शासन के साथ घनिष्ठ सैन्य गठजोड़ कायम करने के लिए साफ तौर पर एक कदम आगे की ओर बढ़ाना है जो दूसरे देशों पर एक के बाद एक हमले कर रहा है, दूसरे देशों की सार्वभौमता का ताबड़तोड़ उल्लंघन कर रहा है, फौजी ताकत की धौंस दिखाकर विभिन्न देशों में तख्तापलट करवा रहा है और विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, डाकेजनी और अंतर्राष्ट्रीय गुण्डागर्दी की अपनी नीति के हिस्से के तौर पर पूरी दुनिया में अपने फौजी अड्डे कायम कर रहा है। 13 अप्रैल के 'द हिन्दू' में भी खबर छपी है कि यह लॉजिस्टिक मदद जिसे दो देशों के बीच नीतिगत रूप से मान लिया गया है पहले 2004 में प्रस्तावित की गई थी जिसे तत्कालीन यूपीए-1 सरकार द्वारा रोका गया था। हालांकि कोई अमेरिकी फौजी अड्डा कायम करने के लिए भारतीय भूमि के इस्तेमाल को एनडीए सरकार द्वारा नकारा जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि दो देशों के बीच सामूहिक सुरक्षा सहयोग को पुख्ता करने के बहाने भविष्य में ऐसे किसी विचार पर सहमति बन सकती है क्योंकि भारत जो पहले से ही साम्राज्यवादी ताकत के रूप में उभर चुका है, दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ अपने सम्बन्धों को अधिकाधिक मजबूत बनाता जा रहा है। एशिया-पेसिफिक में ताकतवर और सापेक्षतः कम ताकतवर साम्राज्यवादी ताकतों के बीच एक मजबूत फौजी गठजोड़ कायम करने की साम्राज्यवादी साजिश चल रही है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल हैं यह इस क्षेत्र में शान्ति के लिए एक गम्भीर खतरा है।

हम भारत के शान्तिकामी साम्राज्यवाद-विरोधी लोगों से आह्वान करते हैं कि वे इस कदम की पूरी तरह निन्दा करें और ऐसे घातक कदमों को रोकने के लिए साम्राज्यवाद-विरोधी जोरदार जुझारू शान्ति आन्दोलन विकसित करें।

130वां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मई दिवस जिन्दाबाद!

मई दिवस नजदीक आ रहा है। पहली मई को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मई दिवस हर तरह के शोषण-अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है, अपने हकों व न्याय के लिये आवाज बुलन्द करने का दिन है, अपनी मांगों के लिये दुनिया के मजदूरों के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करने का दिन है, पूंजीवादी शोषण-जुल्म के जाल को तोड़ फेंकने के लिए एकताबद्ध संघर्ष का दृढ़ संकल्प लेने का दिन है। इस दिन कारखानों, खेतों व खदानों के मजदूर, चिनाई मजदूर-मिस्त्री, बैंक-बीमा-रेल-बन्दरगाह-डाकघर-टेलीफोन के कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर व हैल्पर आदि सभी मजदूर-कर्मचारी अपनी एकता व भाईचारे को मजबूत करने के लिये इकट्ठा होते हैं। मजदूर आन्दोलन पहली मई 1886 से लेकर आज तक अनेक उतार-चढ़ाव देख चुका है। हमें उन सब से सबक लेना है।

मई दिवस का इतिहास

मई दिवस का इतिहास वीरतापूर्ण संघर्षों व कुर्बानियों का गौरवशाली इतिहास है। 19वीं शताब्दी में यूरोप व अमेरिका के कारखानेदार और उनकी ताबेदार सरकार बातें तो न्याय, बराबरी, आजादी व जनतन्त्र की करते थे मगर मजदूरों व अन्य शोषित-पीड़ित मेहनतकशों से बर्ताव गुलामों जैसा किया करते थे। उनको रोजाना 12 घण्टे से भी ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करते थे। इसके खिलाफ मजदूरों ने देश-देश में 8 घण्टे के कार्य-दिवस की मांग उठाई। इस मांग को लेकर 1856 में आस्ट्रेलिया में पहली हड़ताल हुई। दूसरी हड़ताल 1862 में भारत में हावड़ा के 1200 रेलवे मजदूरों ने की। 1886 में 1 मई को अमेरिका में भी 8 घण्टे का कार्यदिवस करने की मांग पर सफल हड़ताल हुई। इससे पूंजीपति वर्ग बौखला उठा और पहली मई को जब शिकागो शहर के हे-मार्केट चौक में मजदूर शान्तिपूर्ण सभा कर रहे थे तब उन पर पुलिसिया दमन चक्र चलाया गया। मजदूरों के बहे खून से झण्डा लाल हो गया। कई मजदूर घायल हुये, बहुत सारे गिरफ्तार कर लिए गये। झूठे केस बनाकर 4 मजदूर नेताओं को फांसी की सजा दी गई। इस घटना ने अमेरिका में 'जनतंत्र' व 'आजादी' के लम्बे चौड़े दावों की पोल खोल दी। इस घटना ने उसके शासक-शोषक वर्ग और उनकी राजसत्ता के क्रूर व घिनौने चेहरे से नकाब हटा दिया। दुनिया के पूंजीपति जिस अमेरिका को धरती का 'स्वर्ग' कहते नहीं थकते थे उसके बारे में इसने लोगों में व्याप्त भ्रम दूर कर दिया। यह कोशिश मजदूर वर्ग के व्यापक राजनैतिक संघर्ष के एक नये स्तर का प्रतीक थी। 8 घण्टे के कार्य दिवस की साझी माँग पर मजदूर वर्ग की विभिन्न पार्टियों, मजदूर संगठनों और लेबर यूनियनों के एकजुट संघर्ष के प्रतीक के रूप में यह दिन उभर कर आया।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

पूंजीवादी शोषण – जुल्म व साम्प्रदायिकता के खिलाफ जनआन्दोलन को मजबूत करने के लिए चुनाव में भाग लेती है वामपंथ की रक्षा हेतु संघर्षशील पार्टी एसयूसीआई(सी)

कॉमरेड प्रभाष घोष की अपील

पूंजीवादी शोषण-जुल्म और साम्प्रदायिकता के विरोध में जनआंदोलन को मजबूत करने के लिये वामपंथ की मर्यादा की रक्षा हेतु संघर्षरत वामपंथी पार्टी एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को विजयी बनायें

(केरल, असम, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल में 2016 विधानसभा चुनाव में एसयूसीआई (सी) के उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित करने के पश्चात् 27 फरवरी को कोलकाता के एक संवाददाता सम्मेलन में महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने अपना वक्तव्य रखा था। 'गणदाबी' के 11-17 मार्च के अंक में प्रकाशित उसी पूर्ण वक्तव्य को यहां प्रकाशित किया जा रहा है। अनुवाद में कोई त्रुटि होने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी– सं. स. दृ.।)

इस विधानसभा चुनाव में पांडिचेरी सहित पांच में से 4 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडू में हम तीन सीटों पर लड़ रहे हैं। वहां सीपीएम और सीपीआई ने हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं किया। उन्होंने कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन किया है। असम में हम 27 सीटों पर लड़ रहे हैं। केरल में पहले से ही हमारी पार्टी एसयूसीआई(सी), आरएमपी और एमसीपीआई (यू)–इन तीन पार्टियों को मिलाकर हमारा एक वामफ्रंट है, जहां हमारी पार्टी 31 सीटों पर लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में सभी जिलों को मिलाकर हम कुल मिलाकर 162 सीटों पर (बाद में और बढ़ी हैं) लड़ रहे हैं। सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) हमारे साथ विचार-विमर्श कर रही है। उम्मीद है, पश्चिम बंगाल में उनके साथ हमारा एक समझौता होगा।

चुनाव हम किस दृष्टिकोण से लड़ते हैं

सबसे पहले मैं इस विषय पर हमारी पार्टी के शिक्षक, संस्थापक तथा महान मार्क्सवादी चिंतक कॉ. शिवदास घोष की शिक्षा के आधार पर कुछ कहना चाहता हूँ। येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतना होगा, सीटें बढ़ानी होंगी तथा जिसके साथ गठबंधन करने से सीटें बढ़ेंगी उसके साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा–एक सच्ची मार्क्सवादी पार्टी होने के नाते इस प्रकार की अनैतिक अवसरवादी राजनीति हमने कभी नहीं की। हमारी पार्टी पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे देश में मजदूर-किसानों और मध्यमवर्गीय जनता की ज्वलंत समस्याओं के निवारण हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। देश की जनता यह जानती है। हम मानते हैं कि मौजूदा समाज व्यवस्था में चुनाव द्वारा जो भी सरकार बने, जनजीवन की किसी बुनियादी समस्या का समाधान न कभी हुआ है, न हो सकता है–जो एकमात्र मौजूदा शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था के क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा ही संभव है। इसके बावजूद भी जब तक हम शोषित जनता को क्रांति के पूरक आदर्श, राजनीति, संगठन तथा नैतिकता से ओत-प्रोत क्रांतिकारी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कॉ. प्रभाष घोष की अपील

(पृष्ठ 1 का शेष)

कार्यकर्ता के रूप में तैयार नहीं कर लेते तब तक बुर्जुआ व्यवस्था में बार-बार चुनाव होगा और राजनैतिक रूप से अनभिज्ञ जनता इच्छा से हो या अनिच्छा से, चुनाव के जाल में उलझती, फंसती रहेगी। इस जनता का चुनाव से मोहभंग करने के लिए तथा जीतने पर विधानसभा-लोकसभा में शोषित जनता के प्रतिनिधि के रूप में मांग उठाने तथा प्रतिवाद ध्वनित करने हेतु और साथ ही बाहर मजदूर वर्ग के संघर्ष और जनआंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से हम चुनाव लड़ते हैं। विश्व साम्यवादी आंदोलन के पथप्रदर्शक महान लेनिन की शिक्षा यही है।

लेकिन सर्वहारा क्रांतिकारी और संग्रामी वामपंथी पार्टी केन्द्र या राज्य में अगर चुनाव जीतकर बहुमत पाकर सरकार गठित करे तो वे क्या करेंगे? ऐसा सवाल लेनिन के समय नहीं उठने के कारण लेनिन कोई गाइडलाइन नहीं दे गये थे। 1967 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार गठित होने से पहले कॉमरेड लेनिन के योग्य छात्र कॉमरेड शिवदास घोष ने इसकी गाइड लाइन दी है। उनके अनुसार एक सच्ची वामपंथी सरकार (1) मजदूर-किसानों और मध्यम वर्ग जनता के जायज आंदोलनों को प्रोत्साहित करेगी, 'लॉ एण्ड ऑडर' के नाम पर अन्य बुर्जुआ पार्टियों की तरह पुलिस के सहारे आंदोलन का दमन नहीं करेगी, (2) नौकरशाही की क्षमता के सहारे नहीं बल्कि संगठित सचेत जनता के सहारे सरकार चलायेगी, (3) भ्रष्टाचारमुक्त पक्षपातरहित प्रशासन चलायेंगी और सरकारी पैसा जनकल्याण के काम में और सबसे ज्यादा गरीबों के हित के काम में लगायेंगी। इन्हीं नीतियों के कारण 1967-69 में पश्चिम बंगाल में जनआंदोलन का ज्वार आया था और 'संयुक्त मोर्चा, जन आंदोलन का हथियार' यह नारा उठा था। 1977 से लेकर 34 साल तक वामफ्रंट सरकार देशी-विदेशी पूंजीपतियों को तुष्ट करने के काम में लगी रहने के कारण वही नारा बन गया था 'वामफ्रंट सरकार जन आंदोलन का दमन करने का हथियार'। देशी-विदेशी पूंजी को तुष्ट करने का वही काम तृणमूल कांग्रेस कर रही है। अन्य जगहों पर तो कांग्रेस और बीजेपी यह काम बहुत पहले से ही कर रही हैं।

आप जानते हैं कि अब तक केन्द्र और राज्य में जिन पार्टियों ने भी सरकार बनायी है वे इसी इरादे से चुनाव लड़ती हैं वे चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के वादे करती हैं। जैसे कि 'गरीबी हटाओ', 'गरीबी निर्मूलन', 'लोकतंत्र की स्थापना', 'सुदिन', 'अच्छे दिन', 'परिवर्तन', 'विकास'–ये सब नारे देकर लोगों को बार-बार ठगा जाता है। बाद में लोग निराश होकर देखते हैं कि हरेक वादा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए होता है। इन दलों का जो वर्ग चरित्र है इससे यही होना स्वाभाविक है।

संसद है, पर लोकतंत्र नहीं

हम यह भी मानते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसने राजतंत्र को उखाड़ फेंक कर कभी घोषणा की थी, तब उसका जो घोषित लक्ष्य था, 'बाई द पिपल', फोर दा पिपल, ऑफ द पिपल' या 'साम्य-मैत्री-स्वाधीनता', उस पर शुरूआत में तो थोड़ा बहुत अमल हुआ लेकिन बाद में यह सिर्फ बात की बात ही रह गयी। यह वास्तव में कहीं भी मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट है परंतु डेमोक्रेसी नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि चुनाव का मतलब जनमत नहीं, यह सिर्फ धन बल, बाहु बल और उद्योगपतियों का ही मत है। वे ही तय करते हैं कि कौन सरकारी सत्ता पर बैठेगा, कौन प्रधान विपक्षी दल होगा। जो सत्ता पर बैठता है वह बुर्जुआ वर्ग का वेतनभोगी सेवादास बनकर सरकार चलाता है। कभी चुनाव द्वारा फिर से नियुक्त होता है तो कभी उन्हें हटाकर किसी और को बैठाया जाता है। दुनिया भर में यही चल रहा है। हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं। शुरूआत में मल्टीकेपीटल या बहुत बड़ी संख्या में छोटे पूंजीपति थे, तब उनकी बहुत सारी पार्टियां थी। उस वक्त बहुदलीय लोकतंत्र या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी। बाद में छोटे पूंजीपतियों को निगल कर मुट्ठीभर एकाधिकारी पूंजीपतियों का अधिपत्य आया, जिससे बहुदलीय लोकतंत्र अब नहीं रहा। उसके बदले आयी है द्विदलीय संसदीय प्रणाली। यह भी याद रखिए कि पार्लियामेंट्री लोकतंत्र का झण्डा फहराकर ही साम्राज्यवादियों ने उपनिवेशों पर कब्जे और लूटपाट चलायी है। दो बार विश्व युद्ध की आग लगायी है। फिलहाल इराक, अफगानिस्तान, लिबिया की आजादी खत्म की है। सीरिया में आक्रमण जारी रखा है। धार्मिक कट्टरवाद को उकसाकर स्थानीय युद्ध चला रहा है। यही है वर्तमान बुर्जुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का असली चेहरा। अत: पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह आज खड़ी है पार्लियामेंट्री फासिस्ट ऑटोक्रेसी।

हमारे देश में अभी देशप्रेम, राष्ट्रवाद को लेकर बहुत शोरगुल हो रहा है। विभिन्न राजनैतिक दल, खासकर दो प्रधान राष्ट्रीय बुर्जुआ दल बीजेपी और कांग्रेस इस बात को लेकर एक-दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है, किसका राष्ट्रवाद कितना है। देश का मतलब सिर्फ मिट्टी-पेड़-नदी-पहाड़ नहीं होता, बल्कि देश की जनता है। तो सवाल उठना चाहिए, उस जनता के प्रति इन दलों की क्या कोई भी जिम्मेदारी या सरोकार है? असल में इनके देशप्रेम का मतलब है सत्ता के प्रति प्रेम और उनके आका कारखानेदारों और धनकुबेरों के प्रति प्रेम। बीजेपी और कांग्रेस बार-बार इसी प्रेम का प्रमाण दे रहे हैं। कांग्रेस 1947 से 1977 तक लगातार केन्द्र की सत्ता पर रही। कांग्रेस शासन का मतलब था देशी पूंजीपतियों का शासन, जोतदारों का शासन, देशी-विदेशी पूंजी की अबाध लूट और शोषण। बीजेपी भी जब-जब सत्ता में आयी है, इसी रास्ते पर चली है। अब भी वही नीति लेकर चल रही है। इनका सारा का सारा ही प्रेम सब कालाबाजारियों-जमाखोरों और काला धन जमा करने वालों के लिए है। करोड़ों असहाय, सर्वहारा, भूखी जनता के लिए सोचने वाला है इनमें कौन है? जनता के लिए क्या किसी की जरा भी कोई सहानुभूति है?

आज देश भयंकर संकट में है, करोड़ों लोग बेरोजगार-अर्धबेरोजगार हैं। पिछले साल एक अखबार में एक खबर थी कि उत्तर प्रदेश में चपरासी के 368 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किये हैं जिनमें से 255 डॉक्टरेट हैं और 25 हजार पोस्ट ग्रेजुएट। यह एक राज्य की तस्वीर है। इसी आधार पर अन्य राज्यों का अन्दाजा लगा लीजिये। यह हाल तो उनका है जो उच्च डिग्रीधारी हैं लेकिन बिना डिग्रीधारियों की खबर किसे पता है। करोड़ों बेरोजगार काम की तलाश में पागलों की तरह घूम रहे हैं। अन्य राज्यों या देशों में पलायन करते जा रहे हैं। यही है विकास, प्रगति। गांव की अशिक्षित महिलाएं भी काम की खोज में यहां-वहां भटक रही हैं। अभाव के कारण घर की महिलाएं देह व्यापार के बाजार में अपना तन बेच कर परिवार पाल रही हैं। हर साल हजारों मजदूर और कर्ज में डूबे किसान खुदकुशी कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 1995 से 2012 के बीच 3 लाख 8 हजार 798 किसानों ने आत्महत्या की है। सूखे या अति बारिश के कारण हर साल किसान को फसलों की बर्बादी भुगतनी पड़ रही है। महंगाई, टैक्स वृद्धि, परिवहन भाड़े में वृद्धि, शिक्षा-इलाज का खर्च दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और इसी का नाम है 'विकास'। उद्योग का संकट पूरी दुनिया में व्याप्त है। बाजार अर्थव्यवस्था का कोई बाजार नहीं है। बाजार का मतलब होता है जनता की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता। जहां आमदनी ही नहीं वहां उत्पादित सामान खरीदने को पैसा आयेगा कहां से। अत: हजारों उद्योग बंद हो रहे हैं। लाखों मजदूरों की छंटनी हो रही है। सरकारी-गैर सरकारी सभी ऑफिस या उद्योगों में स्थायी भर्ती लगभग बंद है। अनुबंध और ठेके यानी कॉस्ट्रैक्ट के तहत ठेका मजदूर लगाए जा रहे हैं। पहले किसी उद्योग में 100 मजदूर काम करने से मालिक को छंटनी-ले ऑफ-तालाबंदी के लिए सरकारी अनुमति चाहिए थी पर अब 300 मजदूर काम करने से भी छंटनी, ले ऑफ या क्लोजर करने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अत: ऐसा कानून लाया जा रहा है कि भारत के 90% उद्योगों के मालिक अपने मन मुताबिक ले ऑफ, छंटनी व तालाबंदी कर सकते हैं। यही है बीजेपी का 'मेक इन इण्डिया'। यही है 'अच्छे दिन'। सरकारी अस्पतालों को बेचा जा रहा है। जहां अस्पताल हैं भी तो जरूरत के मुताबिक डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, इलाज नहीं। दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ाये जा रहे हैं, यहां तक कि कैंसर के साथ-साथ जीवनरक्षक बहुत सारी दवाइयों के लिए आयात शुल्क में छूट दी जाती थी, पर अब नहीं। इलाज का खर्चा वहन करते-करते सिर्फ बीमार आदमी ही नहीं, बल्कि उसका परिवार भी मर जाता है। शिक्षा का खर्च दिन पर दिन बढ़ रहा है। निजीकरण के चलते, शिक्षा बजट, स्वास्थ्य बजट में आये दिन कटौती की जा रही है। बढ़ रहा है मिलिट्री बजट। दूसरी तरफ जहां केन्द्र की बीजेपी सरकार का बजट घाटा 5 लाख 55 हजार 849 करोड़ रुपये का है और देशी-विदेशी कर्जा 68 लाख 94 हजार करोड़ रुपये है, वहीं सरकार उद्योगपतियों की तरफ बकाया टैक्स 5 लाख 2 हजार 852 करोड़ रुपये माफ कर रही है। बैंक से उद्योगपतियों को 6 लाख करोड़ रुपयों की चोरी का मौका दे दिया गया। हर साल करीब 28 लाख करोड़ रुपये का काला धन देश में जमा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी वामफ्रंट सरकार बड़े पैमाने पर कर्जा लेकर गयी है। तृणमूल के शासनकाल में यह बढ़ते-बढ़ते 3 लाख 34 करोड़ होने जा रहा है। अत: राज्य को हर साल सिर्फ ब्याज देना होगा 30,000 करोड़ रुपये। यह पूरी रकम पब्लिक की है। अत: टैक्स और भी बढ़ेगा, चीजों के दाम और बढ़ेंगे। इनका यही है देशप्रेम।

आरएसएस ने आजादी आंदोलन का विरोध किया था

आरएसएस कभी भी आजादी आंदोलन में शामिल नहीं थी। भारत में ब्रिटिश-विरोधी आजादी आंदोलन की बुनियाद पर जो राष्ट्रवाद उभरा था उसे आरएसएस नेता गोलवलकर प्रतिक्रियावादी बताते हैं। आजादी आन्दोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया था क्योंकि आजादी आंदोलन सरासर हिन्दू धर्म पर आधारित नहीं था। इसका अर्थ यह निकलता है कि उनके मतानुसार देशबंधु, सुभाषचंद्र, लाला लाजपत राय, तिलक, भगतसिंह, खुदीराम–इनमें कोई देशभक्त नहीं था। आजादी आंदोलन के वक्त आरएसएस नेतागण कहाँ थे? क्या कभी वे जेल गये थे? कभी मार खायी थी? जिनका इतिहास ऐसा रहा हो, वे देशभक्ति की बात कर रहे हैं।

आजादी आंदोलन में कांग्रेस का राष्ट्रीयतावाद धर्म आधारित था

आरएसएस-बीजेपी जिस तरह से हिन्दू धर्म के आधार पर राजनैतिक झण्डा उठा सकी, इसका प्रधान कारण था आजादी आंदोलन में धर्म के आधार पर राष्ट्रीयतावाद पर अमल होना। बाद में आजाद भारत में लम्बे अर्से से कांग्रेस के शासन काल में कितनी बार जनआंदोलन की शक्ति को तोड़ने की साजिश से और वोट बैंक तैयार करने के हीन उद्देश्य से साम्प्रदायिक दंगे कराये गये थे। ज्यादा दिन नहीं हुए, ऐसा ही दंगा था दिल्ली का सिखों का कत्लेआम और इसी कांग्रेस को सीपीएम धर्मनिरपेक्ष कह रही है। बीजेपी भी साम्प्रदायिकता की आग भड़काकर ही अपनी ताकत बढ़ा रही है। वे अपने को विवेकानंद का शिष्य कहते हैं जबकि विवेकानंद का कहना था, ''ईसाई को हिन्दू या बौद्ध नहीं बनना पड़ेगा। मुसलमान को हिन्दू या बौद्धों को ईसाई नहीं बनना पड़ेगा। ...हम मानव जाति को उस जगह ले जाना चाहते हैं, जहां वेद नहीं, बाइबिल नहीं, कुरान नहीं। मगर वह काम करना होगा वेद, बाइबिल और कुरान को मिलाकर ही।'' उनका कहना था, ''राम और कृष्ण, अयोध्या और मथुरा में जन्म लिये हैं कि नहीं, यह सोच कर दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं, ये सब चरित्र काल्पनिक हैं या ऐतिहासिक यह भी सोचना जरूरी नहीं, जरूरी है रामायण-महाभारत से उच्च शिक्षा प्राप्त करना।''

जिस बीजेपी ने वोट के लिए राम रथयात्रा निकाली, ऐतिहासिक इमारत बाबरी मस्जिद तोड़ी, बार-बार दंगे करवा रही है, वह यथार्थ हिन्दू है या विवेकानंद? विवेकानंद का यह भी कहना था कि भूखे इन्सान को धर्म नहीं रोटी दो। क्या बीजेपी यह काम कर रही है? यह बात भी बहुत लोग जानते नहीं कि बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर पहली रामपूजा करवायी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने हिन्दू वोट हासिल करने के लिए। जब बीजेपी ने बाबरी मस्जिद ढहायी तब केन्द्र की गद्दी पर नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रीत्व में कांग्रेस सरकार बैठी थी, पर कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठायी। इनमें किसी में भी कोई सच्चा धर्म नहीं है, इनका तो सिर्फ एक ही धर्म है, जैसे भी हो वोट हासिल करना।

आज तो देश की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सभी बुर्जुआ

(शेष पृष्ठ 4 पर)

फासीवाद और वाम-जनवादी आंदोलन में नैतिकता का संकट

कॉमरेड शिवदास घोष

(बीजेपी-संघ परिवार के केन्द्र में सत्तासीन होने के चलते देश में फासीवादी शासन का खतरा कई गुना बढ़ गया है। फासीवाद के बारे में कॉमरेड शिवदास घोष ने बार-बार चेतावनी दी थी, फासीवाद का क्या मायना है, किस प्रकार इसकी जमीन तैयार होती है, इस संबंध में उनका सारगर्भित विश्लेषण है। इस तरह की दो चर्चाओं के कुछ अंश यहां दिए जा रहे हैं।)

... फासीवाद क्या है–इसे अच्छी तरह से समझना होगा। फासीवाद के बारे में हमारी पार्टी का एक वक्तव्य हम 1949 से बार-बार बोलते आ रहे हैं। लोगों का एक तबका है जो प्रशासन के उग्र रूप को ही फासीवाद कहता है, तानाशाही को ही फासीवाद कहता है। याद रखें, तानाशाही–मिलिट्री तानाशाही होती है, तानाशाही तख्तापलट के जरिए भी कायम होती है। इसके अलावा, अत्याचार सभी जनस्वार्थ-विरोधी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में होता है, औपनिवेशिक देशों पर साम्राज्यवादी करते हैं। लेकिन फासीवाद उससे भी भयंकर होता है। सिर्फ अत्याचार किसी देश का उतना नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन फासीवाद होता है एक सर्वांगीण प्रतिक्रांतिकारी अभ्युत्थान। एक तरफ यह मनुष्य की चिंतन-भावना आदि को मार कर उसे आत्मकेन्द्रित कर देता है, मनुष्य की ज्ञानविद्या बुद्धि को तकनीक-मुखी बना देता है अर्थात् देश में टैक्नोक्रेटों का एक तबका (शिक्षित कारीगर) तैयार करता है-जो मानवीय उद्देश्य से पूरी तरह विमुख होते हैं और जिनमें लोगों और समाज के प्रति कोई दायित्वबोध नहीं होता है। जो नौकरी और गुलामी को ही सब कुछ मान लेते हैं, पैसे के बदले में वे कुछ भी कर सकते हैं और इसी प्रकार विज्ञान साधना एवं विद्या को वे प्रवाहित करते हैं। दूसरी तरफ हर तरह के अध्यात्मवाद, पुराने जमाने के तमाम कुसंस्कार, हर तरह की तर्कहीन मानसिकता और अंधता को बढ़ावा देते हैं। फासीवाद है अध्यात्मवाद, अंधकारग्रस्त भावना-धारणा एवं तर्कहीनता के साथ विज्ञान की तकनीकी विद्या का एक विचित्र सम्मिश्रण। इस तरह की घटना जब घटती है एवं तर्कशील मन मर जाता है। इसीलिए वामपंथी आंदोलन के संबंध में भी मैंने चेतावनी देते हुए कहा था, जो वामपंथी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चर्चा-बहस का दरवाजा बंद करके बाहुबल प्रयोग करने की नीति अपनाते हैं क्योंकि उनकी ताकत और दलबल ज्यादा होने के चलते इससे उन्हें फौरी तौर पर ज्यादा सहूलियत मिलती है, इसलिए वे किसी को मुंह नहीं खोलने देते हैं, किसी की कोई दलील नहीं सुनते हैं, उनके कार्यकर्ता खुद की तर्क करने की मानसिकता खो देते हैं और दूसरे लोगों के अंदर भी इस मानसिकता को नष्ट कर देते हैं-क्या वे जानते हैं कि इसकी घातक प्रतिक्रिया क्या होती है? असंभव प्रतीत होने पर भी असल में सच यही है कि जो फासीवाद के खिलाफ बात करते हैं, जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, जो वामपंथ की बात करते हैं, संघर्ष-क्रांति की बात करते हैं और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे ही फिर अपने आचरण-व्यवहार के जरिए ऐसी एक तर्कहीन मानसिकता निर्मित करने में मदद कर रहे हैं जिसकी परिणति के चलते इस वामपंथ की ही कब्र खुद जाएगी, फासीवाद का अभ्युत्थान हो जाएगा। क्योंकि देश की धरती पर जब युक्तिवादी मन मर जाता है तभी प्रतिक्रियावादी भावना-धारणा का सामाजिक जीवन में प्रवेश करने का सुगम रास्ता तैयार होता है। एक तरफ अंधराष्ट्रवाद के जहर से लोगों को कट्टरपंथी (फेनेटिक) बना दिया जाए, दूसरी तरफ पुरातनपंथी परम्परावाद और सतही समाजवाद, क्रांति व प्रगति के नारों - इन तीनों को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो किसी देश में फासीवाद की जमीन तैयार होती है। याद रखें, शासक पूंजीपति वर्ग देश के बुद्धिजीवियों को विभ्रांत करके केवल तभी इन तीनों को बढ़िया तरीके से मिला सकेगा जब देश में असल में ही तर्क विज्ञान के आधार पर विचार-विमर्श का मनोभाव सामाजिक जीवन से तिरोहित हो जाए। ऐसे हालात में ही फासीवाद के उभरने का सुनहरा अवसर होता है। इसलिए मैंने वामपंथियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कांग्रेस और शासक वर्ग की पार्टियां देश के अंदर एक तरह की तर्कहीन मानसिकता को पनपाने की कोशिश करेंगे ही। वे तो चाहेंगे ही कि इस तरह की मानसिकता पनपे। लेकिन वामपंथी लोग अपने दलीय स्वार्थ के लिए भी क्यों इस तरह का आचरण करेंगे? यदि करेंगे तो सामयिक तौर पर भले ही यह उनके लिए फायदेमंद हो लेकिन भविष्य में यही उनकी कब्र खोदने का ही मार्ग प्रशस्त करेगा। इसीलिए तर्कहीन मनोभाव के खिलाफ संघर्ष, ज्ञान-विज्ञान-इतिहास की चर्चा, विचार-विमर्श, एक दूसरे के मत पर आलोचना-समालोचना और तर्क-वितर्क का माहौल बना रहना चाहिए। केवल इस तरह का माहौल पैदा होने से ही शोषक वर्ग की किसी भी पार्टी के लिए जनसाधारण में घुसपैठ करना बहुत कठिन हो जाता है।

... यह बात सही है कि देश में खाद्य संकट तीव्र हो रहा है, रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, औद्योगिकीकरण नहीं हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या विकराल रुप लेती जा रही है, बिजली नहीं है – इन तमाम समस्याओं से हम घर-घर में बड़े परेशान और गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन जो इससे भी ज्यादा नुकसानदेह है और जो ज्यादा चिन्ता की बात है वह है गहन संकट जो नीति-नैतिकता में तीव्र गिरावट और तर्कहीन मानसिकता की बढ़ोतरी के चलते हमारे सामाजिक जीवन में दिखाई दे रहा है। याद रखें, अभाव और अत्याचार की मार चाहे जितनी भी क्यों न हो, इससे किसी राष्ट्र को, कौम को मार गिराया नहीं जा सकता है। अंग्रेजों ने 200 वर्ष से ज्यादा अर्से तक हमें अपने अधीन रखा था। लेकिन वे पूरे राष्ट्र को तबाह नहीं कर सके थे। वियतनाम को बमबारी कर अमेरिका ने रेगिस्तान बना दिया था और वहां के लोगों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया था लेकिन वे पूरे देश की, पूरी कौम की रीढ़ को तोड़ नहीं पाये। लेकिन हमारे देश का शासक वर्ग आज देश में क्या सिर्फ आर्थिक दुर्दशा ही पैदा कर रहा है? जिस दलील से वे अपने नाजायज आचरण को जायज ठहरा रहे हैं, लोगों को भी इसका समर्थन करने को कह रहे हैं, पुलिस आये दिन जिस प्रकार खुल्लमखुल्ला कानून को पैरों तले रौंद रही है और राजनैतिक नेतागण और शासकगण पुलिस के इन सब क्रियाकलापों को जिस प्रकार प्रश्रय देते जा रहे हैं, इसके अलावा तर्कहीन मानसिकता यदि ऐसे एक स्तर पर पहुंच जाए कि देश के तरुण भी कुछ समझना न चाहें, गली-मोहल्ले में अभद्र आचरण करें और इसे देखकर वयस्क भी चुप रहें, समाज के तमाम तबके के लोगों में एक-दूसरे के विचारों के प्रति सहनशीलता का ऐसा अभाव पैदा होता रहे, तो इससे क्या साबित है? क्या केवल यही साबित होता है कि हमें भरपेट खाने को नहीं मिल रहा है और हम अभावग्रस्त हैं? क्या यह भी साबित नहीं होता है कि हमारी नैतिक रीढ़ टूटती जा रही है? याद रखें, एक राष्ट्र भूखा-नंगा रह कर भी उठ खड़ा हो सकता है, भूखा रह कर भी वह लड़ता है यदि इन्सानियत रहे लेकिन फासीवाद कायम होने से इन्सान कहने लायक देश में कोई नहीं बचेगा। क्योंकि इन्सान बनने की प्रक्रिया में ही यह बाधा पैदा कर देता है।

... जिस किसी भी उच्च आदर्श की मर्मवस्तु उसके सांस्कृतिक और रुचिगत मान में निहित रहती है। सांस्कृतिक और रुचिगत मान यदि ऊँचा न रहे तो जिस किसी एक उच्च स्तर के राजनैतिक आदर्श का ढांचा भी एक बेजान देह जैसा हो जाता है। कोई शरीर देखने में बहुत खूबसूरत होने पर भी यदि उसमें जान न रहे तो वह जिस तरह बेकार है, लाश को रखे रखना समाज के लिए अनिष्टकर है, ठीक उसी तरह यदि कोई बात तो करता हो किसी उच्च आदर्श की, लेकिन उसमें उन्नत रुचिगत व सांस्कृतिक मान प्रतिफलित नहीं होता है तो वह भी समाज के लिए हानिकारक और पतनशील हो जाता है। इसलिए कोई पार्टी आदर्श की बड़ी-बड़ी बातें कर रही है या नहीं–यह बड़ी बात नहीं है। उनका आदर्श वास्तव में ही महान है कि नहीं–इसका असल सबूत यह है कि उनके नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने व्यक्तिगत जीवन में, रोजमर्रा के व्यवहार में और राजनैतिक आचार-आचरण में उन्नत सांस्कृतिक व रुचिगत मान प्रतिफलित कर रहे हैं या नहीं। इसलिए सीपीआई(एम) यदि असल क्रांतिकारी पार्टी होती तो उसके प्रभाव में बढ़ोतरी के फलस्वरूप समाज में उस सांस्कृतिक स्तर में गिरावट और नैतिक पतन एक कारगर रोक लग गई होती जो पूंजीवाद के ह्रास से शुरू हुआ है। लेकिन ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। बल्कि इसके विपरीत ही होते देखा गया। अध:पतन पर कारगर रोक तो लगी ही नहीं, उल्टे संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में जब सीपीआई(एम) का प्रभाव युवा समुदाय में जबरदस्त बढ़ गया था तब देखा गया कि पहले पहल उसी दौरान छात्रों द्वारा परीक्षाओं में सामूहिक नकल की जाने लगी। उनकी पार्टी में जो युवक आ रहे हैं वे जब नारा देते हैं तो उनकी भाव-भंगिमा अभद्र होती है। जो भी उनकी किसी तरह से भी आलोचना करता है तो उसके प्रति उनके ज्यादातर कार्यकर्ताओं के व्यवहार में जो रुचिगत और सांस्कृतिक मान प्रकट होता है व अत्यंत निम्न स्तर का होता है। उनमें तर्क-विचार में जाने का मिजाज ही नहीं है। इन्सान के तौर पर किसी को मान-सम्मान देना उनकी फितरत में ही नहीं है। कोई विरोध करे तो उसको या तो पीटा जाता है नहीं तो तरह-तरह से अपमानित किया जाता है। तब इन तथाकथित क्रांतिकारियों के आचरण और फासिस्टों, अंध कट्टरपंथियों के आचरण के बीच फर्क कहां है जो समाज में तर्कहीन मनोभाव और अंधता की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं? इसलिए मैंने उस वक्त चेतावनी देते हुए कहा था कि जनसाधारण के अंदर आक्रोश भड़का कर ही क्रांति नहीं होती है। क्रांति वही जनता कर सकती है जो क्रांतिकारी राजनैतिक आन्दोलन में अपनी भागीदारी के जरिये तप कर कुछ हद तक क्रांति की परिपूरक मानसिकता और संस्कृति की अधिकारी हुई है। येन-क्रेन प्रकारेण लोगों को उत्तेजित करने के जरिए ही क्रांति नहीं होती है, इससे क्रांति के नाम पर प्रतिक्रिया की जमीन तैयार होती है। भारत की सरजमीन पर बार-बार ठीक यही सब हो रहा है। नतीजतन, ऐसी घोर गलत राजनीति और क्रियाकलापों की वजह से जो तर्कहीन मानसिकता विद्यमान है उसका फायदा उठाकर आज कांग्रेसी प्रतिक्रिया जबरदस्त घर करती जा रही है। ...

पार्टी यदि क्रांतिकारी पार्टी न हो, उसका रास्ता यदि गलत हो, उसका क्रांति का सिद्धांत यदि गलत हो तो क्रांति-क्रांति के खेल में सारी जनता की कुर्बानी, कार्यकर्ताओं का आत्मत्याग व्यर्थ चला जाता है। नतीजतन जनता विभ्रांत हो जाती है और उसका फायदा उठाकर प्रतिक्रिया फिर से मजबूत हो जाती है। अत: एक गलत राजनीतिक पार्टी–नीति, आदर्श, रुचि, संस्कृति, राजनैतिक विश्लेषण–तमाम पहलुओं से इसके इतिहास की विवेचना करने से देखा जाए कि जिसके अंदर पतन शुरू हो गया है जो पतनशील है आज भी बड़ी पार्टी कहकर यदि इस तरह की पार्टी को ही आप मजबूत करेंगे तो यही बड़ी पार्टी आंदोलन को पथभ्रष्ट करेगी ही और सर्वनाश और भी ज्यादा होगा। कोई पार्टी बड़ी है या छोटी-यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर है लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि पार्टी की राजनीति सही है कि नहीं, पार्टी का चरित्र ठीक है कि नहीं और पार्टी वास्तव में ही क्रांतिकारी पार्टी है कि नहीं।(24 अप्रैल 1973 के भाषण से)

... आपको एक बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि दिन पर दिन खाली पेट, अधभूखी और अधनंगी हालत में रहते हुए भी, शोषण-अत्याचार से जर्जरित होते हुए भी एक राष्ट्र उठ खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है, लड़ने की शक्ति अर्जित कर सकता है, संगठित हो सकता है, सिर ऊँचा करके खड़ा हो सकता है–यदि उस राष्ट्र

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कॉ. प्रभाष घोष की अपील

(पृष्ठ 2 का शेष)

पार्टियाँ सत्ता हासिल करने के लिए हिन्दू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, जात-पात आधारित वोट बैंक, क्षेत्रीयता के आधार पर वोट बैंक की ही राजनीति कर रही हैं।

हमारे देश में कांग्रेस ने पूंजीवाद के हित के लिए फासीवाद कायम किया है जिसे मजबूत बना रही है बीजेपी। यह बात हम बहुत पहले से ही बार-बार कहते आये हैं, इस चुनाव से पहले उसी बात को फिर कहना चाहता हूँ। फासीवाद के भयंकर आक्रमण का मतलब है विचार-विश्लेषण करने का मन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सोच-विचार, सवाल करने, तर्क-बहस करने की मानसिकता को खत्म कर लोगों में अंधविश्वास, धर्मान्धता जगाना। यह काम शुरू किया था कांग्रेस ने और बीजेपी हिन्दुत्व पर सवार होकर इसे और व्यापक पैमाने पर कर रही है।

कांग्रेस के जमाने में राजीव गांधी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी–जो धर्म पर आधारित शिक्षा थी। बीजेपी और एक कदम आगे बढ़कर वैदिक शिक्षा चालू कर रही है, इतिहास को विकृत कर रही है और प्राचीन भारत के हिन्दुत्व का गौरव दिखाने के लिए सच्चाई को तोड़-मरोड़ रही है। गैलिलियो, न्यूटन, आइन्स्टीन से लेकर हाइजेनबर्ग, जगदीशचंद बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सी.वी. रमण, सत्येन बोस, मेघनाथ साहा सरीखे वैज्ञानिकों ने जितने आविष्कार किये थे इनके कहने के मुताबिक यह सभी वैज्ञानिक आविष्कार अतीत में ऋषि-मुनियों ने किये हुए थे–ऐसी ऊटपटांग बात कर रही है।

इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक विज्ञान पर अमल बंद कर देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खत्म करना, विचार-विमर्श करने के मन को मार देना। ऐसा भयंकर आक्रमण हो रहा है पूरे देशभर में। याद रखें, जिस फासिस्ट हिटलर को रवीन्द्रनाथ से लेकर विश्व के सभी मनीषियों ने मानव जाति का दुश्मन माना था, आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने उसी हिटलर को पथ प्रदर्शक मानकर उनका अभिनन्दन किया था।

दूसरा आक्रमण हो रहा है – इन्सानियत को खत्म करो, इन्सान के मूल्यबोध को खत्म करो। मूल्यबोध और संस्कृति विहिन रोबोट बना दो। चेहरे से इन्सान पर नीति-संस्कृति कुछ भी नहीं रहेगी अर्थात बगैर इन्सानियत का इन्सान बनाया जा रहा है। खासकर छात्र-युवाओं को इसी तरफ धकेल दो। अत: पारिवारिक जीवन खत्म किया जा रहा है। सामाजिक जीवन खत्म किया जा रहा है। माया-ममता-दया-इन्सान के जीवन की इस बेशकीमती दौलत को खत्म किया जा रहा है। यह भी फासीवाद का एक हमला है। इन्सान बनने की प्रक्रिया को ही खत्म किया जा रहा है।

तृणमूल सरकार आखिर पूर्व वामफ्रंट सरकार की ही कार्बन कॉपी है

दूसरी तरफ जिस 'परिवर्तन' की बात कर तृणमूल इस राज्य में सत्ता में आयी थी, उस परिवर्तन के नाम पर जो हुआ वह यह कि वामफ्रंट के बदले तृणमूल सरकार सत्ता में आयी है। इसके अलावा और कुछ नहीं बदला। पहले की तरह ही जन आंदोलनों में पुलिस का जुल्म चल रहा है, उन्होंने लाठी मारकर हमारी पार्टी के दो आंदोलनकारियों की आंखें फोड़ दी। तृणमूल राज में पहले की तरह ही बेलगाम महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि, शिक्षा-चिकित्सा खर्च में वृद्धि, हर स्तर पर रिश्वतखोरी और हफ्तावसूली, भ्रष्टाचार का बोलबाला, अपहरण, बलात्कार, खून आदि धड़ल्ले से जारी हैं। सभी क्षेत्रों में वामफ्रंट के दिखाये पथ पर दलतंत्र चल रहा है। हमारी पार्टी इस सरकार की हर जनविरोधी नीति का विरोध कर रही है। वामफ्रंट की सरकार ने पांचवीं कक्षा तक अंग्रेजी और पास-फेल प्रणाली हटा दी थी, इस सरकार ने आठवीं कक्षा तक पास फेल प्रणाली हटा दी। इसके खिलाफ हमारी पार्टी ने पहले भी आंदोलन किया था। 19 साल तक आंदोलन करके अंग्रेजी वापस लाये थे आज भी हम जनविरोधी शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। मूल्यवृद्धि के साथ-साथ वामफ्रंट सरकार जैसा ही इस सरकार ने भी शराब की दुकान खोलने का धड़ल्ले से मौका दे दिया है। टैक्स का बोझ दिन पर दिन बढ़ा रही है। कालाबाजारी-जमाखोरी अबाध चल रही है। महंगाई आसमान छू रही है। बंद कारखाना-चटकल-चायबगान खोलना, छंटनी किये गये मजदूरों को बहाल करना, बेरोजगारों को या तो काम नहीं तो बेकारी भत्ता देना, असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर-कर्मचारियों का वेतन-भत्ता बढ़ाने के लिए हमारी लड़ाई जारी है। शराब की दुकानें, ब्लू-फिल्में, खून-अपहरण-बलात्कार बंद कराने की मांग पर लड़ाई चल रही है। क्षेत्रीय बुर्जुआ दल तृणमूल सरकार इसी रास्ते पर चलेगी–यह हमें पता था इसलिए जब हम एक साथ थे तभी हमने होशियार किया था और कहा था कि इसे सरकारी सत्ता मिलते ही इससे हमारी लड़ाई छिड़ जायेगी और वह लड़ाई हम कर भी रहे हैं।

सीपीएम नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वामफ्रंट को चोट पहुंचायी है

इस परिस्थिति में जहां उन्नत मूल्यबोध और संस्कृति के आधार पर पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पूरे भारत में एक शक्तिशाली वामपंथी आंदोलन संगठित करना जरूरी था, वहीं सीपीएम ने सिर्फ चुनाव के अवसरवादी स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय बुर्जुआ दल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इस पीढ़ी के बहुतेरे लोगों को यह पता नहीं है कि आरएसपी, फारवर्ड ब्लॉक 1950 में संयुक्त वामपंथी आंदोलन में अविभक्त सीपीआई को साथ नहीं लेना चाहती थी जबकि हमारी पार्टी का सुझाव मानकर बाद में सीपीआई को साथ लिया गया। क्योंकि 1942 के अगस्त आंदोलन में सीपीआई ने नेताजी का विरोध किया था इसी वजह से उसे साथ लेने से उन्होंने इन्कार किया था। आप जानते हैं कि अविभक्त बंगाल था भारतीय विप्लववाद का उद्गम स्थल। इस विप्लववाद का आंरभ हुआ था खुदीराम से और इसके प्रतिनिधि थे नेताजी सुभाषचंद्र, यही है वामपंथी आंदोलन की परम्परा। गाँधीजी को दक्षिणपंथी और सुभाषचंद्र को वामपंथी कहा जाता था। पांचवें-छठे दशक में हमारी पार्टी, सीपीआई और अन्य वामपंथी दलों ने मिलकर बहुत सारे आंदोलन संगठित किये थे। पश्चिम बंगाल में जन आंदोलन उफान पर था।

अतीत में संयुक्त वामपंथी आंदोलन के समय हम मार्क्सवादी दल के नाते क्रांतिकारी लाइन और सीपीआई, सीपीआई(एम) यथार्थ मार्क्सवादी न होने के कारण वे वोट सर्वस्व सुधारवादी लाइन लेकर चलती थी। उनके और हमारे बीच वैचारिक मतभेद भी थे। फिर भी उनमें कुछ संग्रामी वामपंथी चरित्र रहने के कारण हमारे साथ उनकी एकता भी थी। हम हमेशा संयुक्त आंदोलन करना चाहते थे क्योंकि एकमात्र वामपंथियों का संयुक्त आंदोलन ही साम्प्रदायिक बीजेपी हो या दक्षिणपंथी कांग्रेस, उनको परास्त कर सकता है। लेकिन वे हमेशा किसी न किसी बहाने हमारा साथ छोड़कर कब किससे चुनावी फायदा उठाया जाये यही मौका देखते रहे। 1977 का चुनाव हम अलग-अलग लड़े थे।

जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में दक्षिणपंथी शामिल हैं यह कह कर जो सीपीआई(एम) उसमें नहीं गयी, वही सीपीएम जनता पार्टी में जनसंघ होते हुए भी उसके साथ चुनाव लड़ी। लेकिन जयप्रकाशजी के आंदोलन में सीपीआई(एम) के साथ हम वामपंथी अगर रहते तो बीजेपी उभर कर नहीं आ पाती। 1977 से 34 साल के शासनकाल में सीपीआई(एम)-नीत सरकार ने बुर्जुआ सरकार जैसा ही काम किया। उसने एक से एक जनविरोधी नीतियाँ अपनायी जिसके खिलाफ जनता की मांगों को लेकर बार-बार हमने आंदोलन किये। इस आंदोलन के दबाव में अंग्रेजी फिर से वापस लागू की गई और बहुत सारी मांगें भी हासिल हुई। सीपीआई(एम) के शासनकाल में हमारे 161 कार्यकर्ता कत्ल किये गए। 49 कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाकर उम्रकैद की सजा हुई। फिर भी हमने सर्वभारतीय स्तर पर केन्द्र सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए वामपंथी एकता की बात कही थी। अन्य राज्यों में भी एकता चाहिए। सीपीआई(एम) नेतृत्व का कहना था कि हमें पहले आंदोलन बंद करना पड़ेगा फिर एकता होगी। मगर हम पश्चिम बंगाल की जनता के हित के लिए आंदोलन बंद करने को राजी नहीं हुए। अत: हमारे साथ उन्होंने एकता नहीं की। संयुक्त वामपंथी आंदोलन संगठित करने के लिए कुछ दिन पहले हमारे पास उनके नेता प्रकाश करात जी आये थे और हमारी 6 पार्टियों की एकता हुई–आप जानते हैं। आंदोलन के लिए हम राजी हुए। हमने उनसे कहा कि पश्चिम बंगाल में हम अभी दो मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू करेंगे–साम्राज्यवाद और साम्प्रदायिकता के खिलाफ। इसे लेकर ही हम चल रहे थे। हमने कहा था कि दक्षिण 24 परगना में हमारी पार्टी के सौ से ज्यादा कार्यकर्ता वामफ्रंट के जमाने में खून हुए हैं। बहुत कार्यकर्ता अभी भी जेल में हैं पूर्व मेदिनीपूर के नंदीग्राम आंदोलन में भी खून से सना अध्याय रचित हुआ था। ऐसी हालत में आने वाले चुनाव में दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर को छोड़कर शेष पश्चिम बंगाल में हम चुनाव में आपके साथ समझौता कर सकते हैं। यह प्रस्ताव हमने दिया था उनको लेकिन उन्होंने हमारे साथ चुनाव को लेकर कुछ भी बात नहीं की। हमने अखबार में देखा है कि वे कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इस गठबंधन से वामपंथी आंदोलन को बड़ी भारी चोट लगी है।

जन आंदोलन का दमन करने में कांग्रेस ने रिकॉर्ड बनाया है

उनके कहने के मुताबिक कांग्रेस एक जनवादी ताकत है। इमरजेंसी, एसमा, मिसा, टाडा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेन्शन कानून, आफस्पा कानून बनाने वाली कांग्रेस आज जनवादी पार्टी बन गयी। भारत के कितने राज्यों में जनआंदोलन को लाठी गोली से दमन करके कितना खून इसने बहाया है। इसी पश्चिम बंगाल में पचास के दशक में ट्राम भाड़ा बढ़ने के खिलाफ आंदोलन, शिक्षक आंदोलन, बंगाल बिहार संयुक्त विरोधी आंदोलन का किस तरह से कांग्रेस सरकार ने दमन किया था। 1959 और 1966 के खाद्य आंदोलन में कितने शहीद हुए थे और आज इसी कांग्रेस को सीपीआई(एम) जनवादी ताकत बता रही है। सिर्फ चुनाव के लिए और इसके द्वारा वह मरी हुई कांग्रेस पार्टी जिसकी पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं थी उसे सर उठाने का मौका दे रही है।

तृणमूल सरकार में है और वह आतंक फैला रही है। यह बात सही है, मगर 1972 साल में जो भयानक आतंक कांग्रेस ने मचाया था उसकी तुलना में यह तो कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि तृणमूल अगर इस बार सरकार बना भी पायी तो अगली बार भी बना पायेगी–इसकी कोई गारंटी नहीं है। केन्द्र और अन्य राज्यों की तरह इस राज्य में भी परिवर्तन होगा। लेकिन कांग्रेस है एक राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टी, जो लम्बे अर्से से पूंजीवाद की सेवा करती आ रही है और पूंजीवाद भी अपने स्वार्थ के लिए उसे मदद करेगा। वामपंथ को त्याग कर सीपीआई(एम) उसी कांग्रेस से समझौता कर रही है।

वे कह रहे हैं कि तृणमूल के आतंक के चलते काम करना संभव नहीं हो रहा है। मैंने उनके एक वरिष्ठ नेता से कहा था कि 1972 में कांग्रेस का जो आतंक था वह तृणमूल के आज के आतंक से भी भयानक था। आप पर हमले हुए थे, हम पर भी हमले हुए थे। उस वक्त हमने जो सामना किया था, आपने भी कुछ हद तक उसका सामना किया था। लेकिन आज आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने जो उत्तर दिया था वह मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। मैंने उन्हें लेनिन की एक शिक्षा याद दिलाते हुए कहा था कि आप जनता के सामने खुले तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिये। इससे जनता का भरोसा आप हासिल कर सकेंगे। यह असल कम्युनिस्ट जैसा काम होगा। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज सीपीआई(एम) के इतने आदमी रहते हुए भी उन्हें क्यों कांग्रेस के सहारे चलना पड़ रहा है। कारण यह है कि जनता कह रही है कि तृणमूल तो सीपीआई(एम) जैसा ही अत्याचार कर रही है। अत: सीपीआई(एम) जनता में जगह नहीं बना पा रही है। जनता का सामना करने से डर रही है। सीपीआई(एम) कभी भी क्रांतिकारी पार्टी नहीं रही। इसलिए क्रांतिकारी राजनीति, क्रांतिकारी संस्कृति पर अमल उन्होंने कभी नहीं किया। फिर अतीत में वामपंथी आंदोलन में रहने के कारण कार्यकर्ताओं में लड़ाई करने का जो मन था, 34 साल सत्ता में रहकर वह भी खो चुका। सरकारी सत्ता न रहने से, पुलिस-प्रशासन साथ में नहीं रहने से, असामाजिक तत्वों पर अपनी पकड़ न रहने से वे लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।

सीपीआई(एम) नेतागण एक बार सोचें, 1964 में आपके हाथ में सत्ता नहीं थी, कभी सरकारी सत्ता की बागडोर हाथ में आयेगी–यह सोचा भी नहीं था, पर तब आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लड़ने की मानसिकता

(शेष पृष्ठ 6 पर)

फासीवाद और वाम–जनवादी आंदोलन में ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

का नैतिक बल अटूट रहे और जनता के सामने एक सही आदर्श कायम रहे। वियतनाम को देखिए, चीन की क्रांति का इतिहास पढ़िए, क्रांतिपूर्व चीन के लोगों की आर्थिक दुर्दशा, अत्याचार, शोषण किस चरम सीमा पर पहुंच गया था–उसे याद कीजिए। लेकिन फिर भी उन सब देशों के लोग, वहां की जनशक्ति उठ खड़ी हुई थी। उठ खड़ी हो सकी थी एक चीज के आधार पर, वह यह कि इतने अत्याचार–उत्पीड़न के बीच भी जनता का चरित्र, राष्ट्र का चरित्र, थोड़ा बहुत नैतिक बल, पुरानी नीति–नैतिकता के आधार पर ही सही, समाज में बचा हुआ था और इसी ने जनता को सही क्रांतिकारी आदर्श को अपनाने और उसी के अनुरूप संघर्ष के उपयोगी नया नैतिक बल हासिल करने के काबिल बना दिया था। इसलिए वियतनाम के अवाम को बम गिराकर बर्बाद नहीं किया जा सका। पूरे देश को रेगिस्तान बना देने पर भी उस देश के भूखे–अधनंगे–अनपढ़ किसानों और जनता का सिर झुकाया नहीं जा सका। बारह–तेरह साल के किशोर–किशोरियों से लेकर वृद्ध–वृद्धाओं तक सभी जी–जान से संघर्ष करने का तेज कहां से पाये थे? वे क्या सभी लेनिन–स्टालिन थे? क्या वे सभी क्रांति के तमाम सिद्धांत बखूबी समझ गए थे? यह तो बिल्कुल निराधार बात होगी। लेकिन एक चीज उनमें थी और है, वह है नैतिक बल व चरित्र जिसके आधार पर वे हर तरह के शोषण के खिलाफ अदम्य साहस के साथ उठ खड़े हो सके थे।

भारत का शासक वर्ग राष्ट्र के इस नैतिक बल व चरित्र को पूरी तरह से तबाह करने की साजिश में लगा हुआ है। वे बहुत ही घाघ हैं। वे जानते हैं कि हजार अत्याचार और दमन–उत्पीड़न करके भी, भूखा रखकर भी किसी राष्ट्र को, देश की जनता को सिर्फ पुलिस–मिलट्री की मदद से ज्यादा दिनों तक दबा कर नहीं रखा जा सकता है। हर जमाने के स्वेच्छाचारी शासकों के अत्याचार का इतिहास यही बताता है कि शोषण–दमन के जरिये, पुलिस राज व मिलिट्री के बल पर आखिर तक जनशक्ति को दबाया नहीं जा सकता है, सत्ता पर कब्जा जमाये नहीं रखा जा सकता है। जनशक्ति सिर ऊँचा कर उठ खड़ी होगी ही यदि उसे सही क्रांतिकारी आदर्श मिल जाए और उनका नैतिक बल अटूट रहे। ...

... आप यह जो सांस्कृतिक पतन देख रहे हैं यह एक संयोग नहीं है। कोई स्वत:स्फूर्त होने वाली बात नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है जो पूर्व निर्धारित एक अवश्यंभावी नियति हो–मानो ऐसा होना ही था और वही हो रहा हो। गहराई से देखने पर पकड़ में आ जाएगा, हालांकि लोगों की नजरों से बच कर यह हो रहा है फिर भी इसके पीछे शासक वर्ग की एक सुनियोजित चाल और संरक्षण है।

मुंह से तो वे लोगों को 'अच्छा बनो, नेक बनो' की बातें कहते हैं फिर व्यावहारिक राजनीति की दुहाई देकर तुच्छ दलगत स्वार्थ में सिर्फ तात्कालिक जरूरतों को सामने रखकर, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ही नहीं बल्कि क्रांति का तमगा लटकाए अनेक पार्टियां भी मनुष्य के अंदर जो नीच प्रवृत्तियां होती हैं उन्हीं को बढ़ावा दे रही हैं। संघर्ष और लड़ाई के नाम पर कायर की तरह हमला करने की प्रवृत्ति को, दस लोग मिलकर एक को मारने के नीच क्रियाकलाप को, सैद्धांतिक चर्चा और तर्क–विचार की बजाय असहिष्णुता की प्रवृत्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। लोभ–लालच और नीचता जो किसी आदमी को हैवान बना देती है, उसकी वीरता और असल मर्यादाबोध को नष्ट कर देती है, उसी को आज बढ़ावा दिया जा रहा है। पैसे के बदले काम करने वाले कार्यकर्ताओं से पार्टी या ट्रेड यूनियन का नियमित कार्य कराये जा रहे हैं। चुनावी काम कराया जाता है। यह सब व्यावहारिक राजनीति की दुहाई देकर कराया जा रहा है। लाखों–लाख बेरोजगारों से आज सारा देश भर गया है। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए ये राजनीतिक पार्टियां उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह उन्हें 'नौकरी' दी जा रही है। आप लोग जानते हैं कि सभी मनुष्य गुण–दोष लेकर ही मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर जो अच्छे पहलू रहते हैं अर्थात् उसमें - साहस, वीरता, सहानुभूति, उदारता और कर्तव्यबोध के जो पहलू रहते हैं उन पहलुओं को बढ़ाने में मदद करके ही उसके दोषों को दूर किया जा सकता है। सिर्फ दोष को दूर करने की बात करने से तो दूर नहीं हो जाते हैं या मनुष्य को नेक बनो का उपदेश देने से ही तो मनुष्य नेक या अच्छा नहीं बन जाता है। फिर एक तरफ 'ईमानदार बनो, अच्छे बनो' का यह उपदेश और दूसरी तरफ व्यावहारिक राजनीति की दुहाई देकर कोई व्यक्ति या पार्टी, कथनी में उनके जो भी क्यों न हो पर करनी में मनुष्य के अंदर की नीच प्रवृत्तियों को उकसा कर, इसके जरिये जाने–अनजाने, असल में वे पूरे देश के सांस्कृतिक परिवेश को, राष्ट्र के नैतिक चरित्र को ध्वस्त करने का जो बुर्जुआ वर्ग का षड्यंत्र है उसी को सफल करने में मदद कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर वे स्वयं ईमानदार हैं या बेईमान–यह उतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है।

यदि स्थिति यह हो तो राष्ट्र की नैतिकता मिटेगी ही। नैतिकता के बिना क्रांति नहीं हो सकती। जो लोग यह सोचते हैं कि लोगों की आर्थिक दुर्दशा और उन पर अत्याचार–उत्पीड़न बढ़ने से अपने आप क्रांति हो जाएगी–मैं कहूंगा, वे मूर्ख हैं। वे जानते नहीं हैं कि किसी भी देश में भिखारी कभी क्रांति नहीं करते। क्रांति करती है शोषित जनता। इस बात का एक मायने है। लुम्पेन लोग क्रांति नहीं करते हैं बल्कि सभी देशों में लुम्पेन लोग बुर्जुआ वर्ग के हाथों, फासीवादियों के हाथों क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रिया की फौज के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। इसलिए मार्क्स से लेकर लेनिन, माओ–त्से–तुंग तक सभी का यही कहना था कि आर्थिक दुर्दशा की वजह से सर्वहाराओं के अंदर जो लोग 'लुम्पेन' बनते जा रहे हैं वे हमारे कोई नहीं हैं, वे सर्वहारा क्रांतिकारी नहीं हैं। क्रांतिकारी सर्वहारा को क्रांति के लिए इस लुम्पेनगिरीं के खिलाफ लड़ना पड़ता है। इसीलिए अभाव रहने से ही इससे विस्फोट की तरह क्रांति फूट नहीं पड़ती है। जो फूट पड़ता है वह विक्षोभ है। इसके द्वारा आखिर तक शोषकों का ही ज्यादा फायदा होता है। रास्ता भ्रांत, नेतृत्व गलत, सिद्धांत गलत, क्रांति के संबंध में स्वच्छ व सही राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं–ऐसी असंगठित जनता की लड़ाई जब संगठित राजसत्ता के दमन के सामने परास्त होती है तब पराजय का मनोभाव छा जाता है। लोगों में संघर्ष का जो जज्बा था, आवेग था वह इस तरह निश्शेषित हो जाने के फलस्वरूप हताशा और पराजय का मनोभाव जन आन्दोलनों को, भले ही कुछ समय के लिए हो, ग्रसित कर लेता है। अत: यह शोषक वर्ग के लिए सबसे सुविधाजनक होता है। इसका फायदा उठाकर शोषक वर्ग अपना काम बना लेता है। अपनी शासन व्यवस्था और राजनैतिक संगठन को कुछ हद तक और भी मजबूत कर लेता है। . . .

आप जानते हैं, पूरे देश में इस तरह अनेक 'लाल किले' तैयार हुए थे मानो वे किसी एक विशेष पार्टी या संगठन की जागीर हों–वहां दूसरे किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं, यदि कोई अच्छी बात भी कहे तो चूंकि वह पार्टी का आदमी नहीं है, क्योंकि वह हमारा किला है, इसी वजह से उसको घुसने नहीं दूंगा या उसकी सही बात पर भी ध्यान नहीं दूंगा–यह कैसी बात है? हो सकता है कि वह चर्चा, आलोचना–समालोचना मुक्ति आंदोलन के ही काम आती लेकिन चूंकि किला बना लिया गया है, इसी वजह से कान में तेल डाल लेना या ताला लगा लेना क्या ठीक बात है? नेतागण कह रहे हैं हर स्तर पर किले कायम करो–इसका मायने क्या यह है कि उसमें बुद्धि भी प्रवेश न कर सके। इसका नतीजा क्या निकला? इसके चलते अंधता बढ़ रही है। अंधता की मनोवृत्ति फासिस्ट सुलभ है–यह बुर्जुआ वर्ग की ही मदद करती है। श्रमिक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन अज्ञानता का कारोबार नहीं करता। वह युक्तिहीनता का कारोबार नहीं है। वह युक्ति, तर्क–वितर्क, चर्चा–बहस, आलोचना और वैचारिक संघर्ष में विश्वास रखता है क्योंकि वे सच्चाई की खोज करने वाले लोग हैं। आलोचना, युक्ति, तर्क–वितर्क से वे नहीं डरते हैं। केवल वही लोग आलोचना को दबाना चाहते हैं, निरुत्साहित करना चाहते हैं जो गलत जगह पर हैं, जो प्रतिक्रियावादी हैं। इसीलिए वे कभी अनुशासन की दुहाई देकर, कभी एकता की दुहाई देकर, किले–विले तैयार करने की बातें कहकर असल में वे चर्चा–बहस को ही दबाना चाहते हैं। वे तर्क–वितर्क से डरते हैं, युक्तिसंगत विचार–विश्लेषण से डरते हैं। जब वे किसी आदमी को भाषण में विश्लेषण करते हुए देखते हैं तो मजाक उड़ाकर कहते हैं–क्लास ले रहा है। मानो सिर्फ भड़काने या उत्तेजित करने के लिए ही भाषण देने की जरूरत है। इसके बाद फिर भले ही उत्तेजित होकर लोग यहां–वहां छिटपुट लड़ाई–भिड़ाई में मरें। मरती है तो जनता ही, नेता तो नहीं मरते हैं। इन नेताओं में कौन, कब गोली खाकर मरे हैं? वे नहीं मरते हैं। कभी–कभी क्रांतिकारी मरते हैं। लेकिन इन सब नेताओं को तो पुलिस 'सर सर' कहते हुए सिर पर उठाए रखती है, चारों तरफ से घेर कर रखती है। इसीलिए ये सब नेतागण सिर्फ लोगों को केवल भड़काते हैं, उत्तेजित करते हैं और भड़कने पर जितने ज्यादा लोग मरते हैं, उतना ही इन सब नेताओं के लिए अच्छा होता है। दो एक के शहीदी दिवस मनाकर शासक पार्टी को गाली–गलौज करके इन सब नेताओं को चुनाव की वैतरणी पार करने का मौका मिल जाता है। ...

संघर्ष, आन्दोलन तो आप लोगों को करना ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग लड़ेंगे नहीं। पेट बड़ी बुरी बला है। आज यदि सोचें भी कि संघर्ष करने से, लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, फिर भी दो दिन बाद ही लड़ाई के मैदान में आप लोगों को उतरना ही पड़ेगा। अभी से इसका आभास मिल रहा है। हजारों–हजार लोग जंग के मैदान में उतरेंगे, लड़ाई शुरू करेंगे लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं होगा। हालात बदलने के लिए उन्हीं तीन चीजों की जरूरत होगी–सही मूल राजनैतिक लाइन तथा नजरिया, सही क्रांतिकारी सिद्धांत और सही क्रांतिकारी पार्टी। ये यदि न रहें, रास्ता यदि गलत हो तो ईमानदारी, कुर्बानी, संघर्ष आदि कुछ भी रहे आप आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इसीलिए लेनिन का वह कथन याद दिलाते हुए मैं एक बार फिर कहता हूँ–चाहे जितने भी जनवादी आंदोलन करें, मांगों को लेकर चाहे जितना भी लड़ें, शहीदी दिवस मनायें, सीने का कितना ही खून उड़ेल दें, हड़तालों और आंदोलनों में पुलिस के साथ कितना ही मुकाबला करें–आप लोग जैसे गुलाम हैं, वैसे गुलाम ही रह जाएंगे। पूंजीवाद जस का तस रह जायेगा, शोषण निर्बाध बरकरार रह जायेगा। तनख्वाह हो सकता है दस–बीस रुपये बढ़ जाए। लेकिन बाजार में सामानों के दाम ऐसे ही ज्यादा हैं इससे भी कई गुना महंगाई बढ़ जायेगी। फिर तनख्वाह बढ़वाने के लिए लड़ोगे, खून बहाओगे, तनख्वाह पांच रुपये बढ़ेगी, लेकिन फिर सामानों के दाम बढ़ जायेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं–यह अनिश्चियता, उद्देश्यहीनता नैतिक जीवन में भी पतन ला देगी। जिस सुख का सपना लेकर परिवार का पालन–पोषण कर रहे हो, परिवार में आपके अत्यंत घनिष्ट संबंधों पर भी मौजूदा समाज की जो सामाजिक व्याधियां हैं उनकी छाया पड़ेगी ही, वे सब उसमें घुस जाएंगी। आपने सुख की कल्पना करते हुए, अनेक सपने लेकर जो घर बसाया था उस घर में जाकर देखेंगे कि वह घर–संसार भी बचा नहीं, वहां भी सुख–चैन नहीं है, प्यार–मोहब्बत नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। जिन बाल–बच्चों के पालन–पोषण के लिए आपने अनेक कष्ट झेले, किसी बात की कोई परवाह नहीं की, देखेंगे कि उनमें से एक–एक मूर्ति नमूने की है–कोई तो सिनेमा के हीरो का 'फैन', कोई कहीं के किसी खिलाड़ी का 'फैन' बन बैठा है। अर्थात् यूं कहें कि आप अपने आत्मीय स्वजनों, निकट संबंधियों, रिश्तेदारों को लेकर ही लगे रह कर एकदम निर्लिप्त भाव से हर किसी मामले से दूर रह कर, कभी किसी तीन–पांच में नहीं उलझकर, किसी झंझट–झमेले में नहीं पड़ कर, राजनीति में नहीं आकर, किसी आन्दोलन में भी भाग नहीं लेकर, सिर्फ नौकरी–चाकरी करते हुए और खाने–पीने व सोने में दिन बिताते हुए खुद को इसके चंगुल से बचा नहीं पायेंगे। सामाजिक समस्या का भूत आपके घर में घुस जाएगा ही। आपके व्यक्तिगत जीवन को विषाक्त कर देगा। प्यार–मोहब्बत खत्म कर देगा। आपके स्नेह–ममता को ध्वस्त कर देगा। अत: बचने के लिए संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। और यह संघर्ष क्रांति के रास्ते पर करना होगा। क्रांति के रास्ते का मतलब 'क्रांति' 'क्रांति' चिल्लाना नहीं है। यदि आप क्रांति का सही स्तर तय कर पाये, देश के वर्ग–विन्यास के बारे में सही सुस्पष्ट शिक्षा से यदि शिक्षित कर सके तभी आप जनता की राजनैतिक शक्ति को जन्म दे सकेंगे, राजनैतिक क्षमता को पैदा करने में सक्षम होंगे एवं राजनैतिक क्षमता के अधिकारी होंगे। तभी आएगी वह शुभ घड़ी जब भारतवर्ष के करोड़ों–करोड़ शोषित–पीड़ित लोग क्रांति का मुंह देखेंगे। उससे पहले तक सिर्फ विक्षोभ और पराजय ही होगी। सिर्फ विस्फोट और हार। इनके चगुंल से मुक्ति, समाज की मुक्ति, जनमुक्ति का रास्ता एक ही है–वह है क्रांति का रास्ता। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

(17 मार्च 1974 को श्रमिक सभा में दिये गये भाषण से)

कॉ. प्रभाष घोष की अपील

(पृष्ठ 4 का शेष)

थी, जिस मानसिकता को लेकर हमारे साथ 1965 में ऐतिहासिक खाद्य आंदोलन में आपके कार्यकर्ता लड़े थे, जिस खाद्य आंदोलन में कांग्रेसी अत्याचार को देखते हुए घृणा से जनता ने 1967 के चुनाव में कांग्रेस को परास्त किया था। आज 34 साल लगातार सरकार में रहकर भी सिर्फ एक बार हार जाने से आपकी पार्टी की ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई कि आपको कांग्रेस का हाथ थामकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 34 साल रही वामफ्रंट की सरकार में आपकी ताकत बढ़ी या घटी? घटी तो क्यों घटी? सरकार सत्ता में रहे तो ताकत बढ़ जाती है, नहीं रहे तो घट जाती इसका कारण यह है कि अतीत में पार्टी में आदर्शवाद पर जो थोड़ा-बहुत अमल होता था, लड़ाई के लिए प्रबुद्ध किया जाता था, वह सब बंद हो चुका है। जुझारू वामपंथ का रास्ता वे छोड़ चुके हैं। अभी उनका एकमात्र उद्देश्य है जैसे भी हो चुनाव में सीटें बढ़ाना, सरकार गठन करना।

तिरंगा झण्डा और लाल झण्डा लेकर एकसाथ सभा-जुलूस? सीपीआई(एम) के कार्यकर्ता जरा सोचें

सीपीआई(एम) की सीट बढ़ें या घटें, जो भी हो, पर यह बात भी मैं कह रहा हूं कि अभी सीपीआई(एम) की जो कुछ बची-खुची ताकत है, वह भी इस रास्ते को अपनाने के कारण वह बचा नहीं पायेगी। ये बात नेताओं को सोचनी चाहिए। सीपीआई(एम) में जो नेता या कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अब तक दक्षिणपंथी और वामपंथी में जो फर्क था उसे सीपीआई(एम) नेताओं ने चुनाव के सुविधावादी स्वार्थ के लिए मिटा दिया। यहाँ तक कि तिरंगा और लाल झण्डा साथ लेकर मीटिंग कर रहे हैं। सम्पूर्ण बंगाल में बड़े-बड़े दक्षिणपंथी कांग्रेसी नेता, यहाँ तक कि गाँधीजी-नेहरू तक जगह नहीं बना पाये थे। गाँधीवादियों ने बंगाल के क्रांतिकारियों को कोई सम्मान नहीं दिया था। नेताजी को कांग्रेस सभापति पद छोड़ने पर मजबूर किया था। कांग्रेस से सस्पेंड कर उन्हें निकाल दिया था। इसलिए स्वदेशी आंदोलन के समय और उसके बाद भी जनता में, खासकर शिक्षित जनता में वामपंथ की लहर थी, दक्षिणपंथियों के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं किसी बैरभाव, द्वैष से यह बात नहीं कह रहा हूँ, दर्द के साथ, चिंता के साथ मैं यह सब कह रहा हूँ। आपके शासनकाल में हमारे इतने कार्यकर्ता कत्ल हुए हैं। हमने कहा था कि वामपंथी एकता की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका विस्तार होना चाहिए। इसे धीरे-धीरे मजबूत बनाना पड़ेगा, पर उनकी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के चाहने के बावजूद सीपीएम नेतृत्व उस रास्ते पर नहीं चला, उस रास्ते से हट गया जिससे वामपंथी आंदोलन को बड़ी भारी चोट पहुंची।

वामपंथ की मर्यादा की रक्षा करने के लिए ही हमने चुनाव में हिस्सा लिया है

ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी चुनाव में अकेले लड़ रही है वामपंथ की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, संग्रामी वामपंथ की परम्परा की रक्षा करने के लिए। हमने हिस्सा लिया है मजदूर-किसान-मध्यमवर्ग के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए। जनतांत्रिक आंदोलन की शक्ति को बढ़ाने के लिए। भारत और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इस फासिस्ट आक्रमण के खिलाफ जो बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्, पत्रकार, चिंतनशील वर्ग ऊंची आवाज में प्रतिवाद कर रहे हैं, उनके इस प्रतिवाद की आवाज को मजबूत बनाने के लिए। हम इसी बात को लेकर चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास करते हैं कि पश्चिम बंगाल के शुभबुद्धिसम्पन्न लोग, वामपंथी चेतनासम्पन्न लोग, जनतांत्रिक चेतनासम्पन्न लोग हमारा साथ देंगे। हम चाहते तो कांग्रेस-सीपीआई(एम) गठबंधन में शामिल हो सकते थे। कुछ सीटें हमें मिल जाती, हम चाहते तो तृणमूल के साथ भी जा सकते थे इससे भी हमें कुछ सीटें हासिल हो जाती। लेकिन उस रास्ते पर हम गये नहीं। हम चुनाव की राजनीति को इस दृष्टिकोण से नहीं देखते। चुनाव हमारे लिए एक आंदोलन है। एक लड़ाई है, नीति-आदर्श के बल पर लड़ाई है। हमारे लिए सौ एमएलए-एमपीओं से खुदीराम, भगतसिंह, अशफाकउल्ला खां, प्रीतिलता ज्यादा कीमती हैं जिन्होंने अपनी जान देकर क्रांति का झण्डा फहराया है। सीटें मिले तो अच्छा, न मिलने से भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष के चिंतन के आधार पर।

आज भारत की अन्य जगहों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल का माहौल भी कितना भयंकर है। शराब, जुआ, ड्रग के नशे में छात्र-युवा समाज को डुबाया जा रहा है। पितृत्व-मातृत्व असम्मानित है, नारी की इज्जत खतरे में है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, कत्ल बढ़ रहे हैं। बच्ची हो या बुढ़ी, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। किसने इन बदमाशों को जन्म दिया। मरणोन्मुख पूंजीवाद इन सबको जन्म दे रहा है। लम्बे अर्से से पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी शासन, सीपीआई(एम) शासन, तृणमूल शासन चल रहा है। उनके शासन काल में यह सब हो रहा है। यह सब देखकर सवाल उठता है कि क्या सचमुच यहाँ राममोहन-विद्यासागर-विवेकानंद-रवीन्द्रनाथ-शरत्चंद्र-नजरूल-देशबंधु-सुभाष-खुदीराम-प्रीतिलता जैसे लोगों का जन्म हुआ था? तृणमूल भी परिवर्तन का जो नारा लेकर आयी थी कहाँ है वह परिवर्तन? तृणमूल ने जो नया कुछ किया है वह है कन्याश्री, युवाश्री, छात्रश्री, साइकल देना, जूता देना –यह सब। इससे वोट में उनकी कुछ श्रीवृद्धि हो सकती है, कुछ लोग बहक सकते हैं, पर पूरे देश की तरह पश्चिम बंगाल भी श्रीहीन काले-अंधेरे में डूबता जा रहा है।

एसयूसीआई(सी) की शक्ति का उद्गम क्रांतिकारी आदर्श, उन्नत नैतिक बल और आम आदमी का बेशर्त समर्थन और प्यार

अत: हम लड़ रहे हैं केन्द्र की बीजेपी के जनविरोध ी बुर्जुआ शासन के खिलाफ। राष्ट्रीय बुर्जुआ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ, तृणमूल के कुशासन के खिलाफ और सीपीआई(एम) की सुविधावादी राजनीति के खिलाफ। इन सबके विरुद्ध है हमारी लड़ाई।

हम यह भी जानते हैं कि अन्य सभी पार्टियाँ उद्योगपतियों, बड़े व्यापारियों, कालाबाजारियों के धन बल पर चुनाव लड़ती हैं। उस पैसे से वे अपराधियों को इस्तेमाल करती हैं। मालिक वर्ग द्वारा नियंत्रित समाचार पत्र, टीवी चैनल उन्हीं का प्रचार करते हैं। चुनाव आयोग भी चुनाव के पहले फ्री-फेयर-इलेक्शन के नाम पर बहुत डीगें हांकता है पर रिगिंग, चुनाव धांधली भी चलती है। इसके खिलाफ गरीबों की पार्टी के तौर पर हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हमारी शक्ति की प्रेरणा पार्टी का क्रांतिकारी आदर्श, उन्नत नैतिक बल और आम आदमी का बेहिचक समर्थन और प्यार। इससे बड़ी ताकत और कुछ नहीं होती। इसी दृढ़विश्वास के साथ हम लड़ रहे हैं।

जनता से, छात्र-नौजवानों से हमारी पुरजोर अपील है कि झूठी बातों के बहकावे में मत आइये, पैसे के लालच में अपने को बेचिए मत। इज्जत और इन्सानियत के साथ सर उठा कर रहें। हर जमाने के महापुरुषों को, ब्रिटिश शासित युग के मनीषियों को, क्रांतिकारियों को याद कीजिए। आज पूंजीवाद देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन, इन्सानियत, नारी सुरक्षा, स्नेह ममता सब कुछ को खत्म कर रहा है। इससे अगर छुटकारा पाना है तो चाहिए पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति। सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा स्थापित एसयूसीआई(सी) पार्टी उसी क्रांति का परचम लहरा रही है। इस पार्टी को शक्तिशाली कीजिये। चुनाव में भी समर्थन दीजिए।

रिपोर्टरों के प्रश्नों के उत्तर

संवाददाता : प्रभाष बाबू आप एवं आपके साथ सीपीआई-एमएल(लिबरेशन) रहेगी, किन्तु आप तो सरकार नहीं बना पायेंगे, उस अवस्था में तृणमूल सरकार या कांग्रेस-सीपीआई(एम) की संयुक्त सरकार आने पर आप अधिक खुश होंगे या दुखी होंगे?

प्रभाष घोष : हमारे खुश होने या दुखी होने का कोई कारण नहीं है। कोई भी सरकार आये आम जनता के लिए कुछ नहीं करेगी। लड़ाकू वामपंथी आंदोलन से बनकर यदि कोई सरकार आए, पूर्ववर्ती संयुक्त मोर्चा सरकार की परम्परा लेकर आए तो ही एकमात्र वही सरकार कुछ कर पायेगी।

संवाददाता : प्रभाष बाबू एक आरोप आपकी पार्टी पर लगेगा, वह यह कि आप अपनी पार्टी को विपक्षी पार्टी बताते हैं तो विरोधी वोट काट कर तृणमूल को आने में सुविधाजनक रास्ता बना दे रहे हैं?

प्रभाष घोष : जो लोग हमारा समर्थन करते हैं, उनका वोट हमें मिलेगा। दूसरों का वोट हम क्यों काटने जायेंगे? हमारी पार्टी को जो लोग समर्थन करेंगे, हमारे वक्तव्य का समर्थन करेंगे, वे हमें वोट देंगे। वोट तो किसी की पॉकेट में नहीं है, वोट तो आम जनता देती है। जनता जिसे समर्थन देगी, वोट उसको ही देगी। किसी का वोट छीन लेना हमारे अधिकार में नहीं है। अन्य लोग प्रचुर रुपये लेकर चुनाव में उतरते हैं, रुपये देकर वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, शराब-मांस खिलाते-पिलाते हैं। हम लोग इस तरह के कुकर्म नहीं करते हैं – देश की जनता यह बात जानती है। केवल हमारी पार्टी ही है जो सड़कों पर खड़े होकर, घर-घर जाकर चंदा मांगती है एवं इस तरह पार्टी का प्रचार करती है, आंदोलन के समय भी करती है, चुनाव के समय भी करती है।

संवाददाता : आपने इससे पहले तृणमूल के साथ चुनावी गठबंधन किया था, फिर सीपीआई(एम) अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं?

प्रभाष घोष : हम तृणमूल कांग्रेस के साथ एकजुट क्यों हुए थे, इसका उत्तर बहुत बार पब्लिक मीटिंग में दिया है। आपको भी जितना हो सकेगा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। प्रथमत:, हम वोट के लिए एकजुट नहीं हुए थे। बहुत लोग जानते हैं, हमारी पार्टी ने ही सिंगुर-नंदीग्राम से आंदोलन शुरू किया था, इस आंदोलन पर वामफ्रंट सरकार ने बुरी तरह आक्रमण किया। उस समय तृणमूल इस आंदोलन में भाग लेने के लिए हमारे साथ एकताबद्ध होना चाहती थी। जबकि हमारा लक्ष्य और उनका लक्ष्य अलग था। हम क्रांतिकारी पार्टी के रूप में, जनता को जागरूक और लामबंद कर मांग पूरी कराने के लिए अंत तक लड़ते हैं और उनका लक्ष्य था आंदोलन के प्रभाव का लाभ उठाकर सरकार-विरोधी मनोभाव को वोट के लिए इस्तेमाल करना। यह हम जानते थे। किन्तु हम अकेले वामफ्रंट सरकार के आक्रमण का मुकाबला कर आंदोलन की रक्षा नहीं कर पाते। इसके अलावा हमारे आंदोलन करने पर बुर्जुआ मीडिया प्रचार नहीं देते, बल्कि उनकी पसंदीदा पार्टी तृणमूल को देते। इस परिस्थिति में आंदोलन के स्वार्थ में हमने तृणमूल के साथ गठबंधन किया था, तब भी शुरू में पार्टी के स्तर पर उन लोगों के चाहने पर भी एकजुट नहीं हुए थे। सिंगुर 'कृषि जमीन रक्षा कमेटी' और नंदीग्राम भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी' इन जन कमेटियों के माध्यम से आंदोलन किया गया। इससे पहले तृणमूल जब अकेले आंदोलन में थी, तब धरने, पदयात्रा, अनशन आदि के माध्यम से कोई भी मांग पूरी नहीं करा पायी। किन्तु हमारे साथ होने की वजह से दोनों जगह निचले स्तर से जनकमेटी और वालंटियर वाहिनी गठित कर दीर्घस्थायी आंदोलन किया जा सका। यदि आप जानना चाहते हैं, सच्चाई यह है कि हमारी पार्टी की सहायता से सिंगूर के गरीब किसानों, नर-नारियों ने दो दिन तक पुलिस की मार खाकर भी प्रतिरोध किया था। अगर अंत तक इस तरह से आंदोलन को चला पाते तो सिंगुर में वामफ्रंट सरकार जमीन पर कब्जा कर टाटा को नहीं दे पाती, लेकिन तृणमूल इस तरह से आंदोलन करना नहीं चाहती थी। उनकी नेत्री ने अनशन शुरू कर प्रचार करवा दिया कि अनशन के द्वारा मांग पूरी होगी। इस तरह से प्रतिरोध के आंदोलन को रुकवा दिया। उसका लाभ उठाकर वामफ्रंट सरकार ने जमीन पर कब्जा कर लिया। हमने उस समय भी तृणमूल की इस भूमिका की खुलेआम आलोचना की थी। किन्तु अकेले आंदोलन लगातार चलाने लायक उस जगह पर हमारा संगठन नहीं था। इसके फलस्वरूप आज भी जमीन से बेदखल सिंगूर के किसान कष्ट पा रहे हैं। तृणमूल की मुख्यमंत्री ने तो बोल दिया, जमीन वापस लाने के लिए पचास वर्ष भी लग सकते हैं कानूनी लड़ाई लड़ने में। तृणमूल सरकार गठन के बाद मैंने प्रस्ताव दिया था कि किसान अपनी जमीन पर कब्जा कर ले, पुलिस रुकावट न डाले और सरकारी कानूनी राय भी आप जानकर फिर उसे मान ले। किन्तु तृणमूल का काम निकल गया, मंत्रित्व मिल गया, फिर उस रास्ते पर वे लोग वापस लौटे ही नहीं।

किन्तु नंदीग्राम में प्रतिरोध आंदोलन को तृणमूल का नेतृत्व रोक नहीं पाया, क्योंकि वहां हमारा संगठन अपेक्षाकृत मजबूत था एवं स्थानीय तृणमूल का नेतृत्व हमारी पार्टी द्वारा प्रतिरोध करने के कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझ गया था। इस वजह से नंदीग्राम का आंदोलन विजयी हुआ।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कॉ. प्रभाष घोष की अपील

(पृष्ठ 6 का शेष)

इस प्रसंग में एक बात और कहना चाहूंगा, मार्क्सवाद की शिक्षा है, वोट के स्वार्थ में नहीं, आंदोलन के स्वार्थ में आवश्यकता के अनुसार दक्षिणपंथियों के साथ सामयिक एकता की जा सकती है। जैसे महान लेनिन ने 1905 में रूस के जार के विरोध में एक प्रतिक्रियावादी पादरी के नेतृत्व में संचालित मजदूर-किसानों के विक्षोभ प्रदर्शन में कम्युनिस्टों ने भाग लिया था। कारण मांग जनतांत्रिक थी एवं नेतृत्व देने वाले प्रतिक्रियावादी चरित्र को उजागर करने की आवश्यकता थी। ठीक इसी वजह से 1974-75 में जयप्रकाश के आंदोलन में दक्षिणपंथी थे, ये जानते हुए भी हमारी पार्टी शामिल थी और हमने सीपीआई(एम) को भी शामिल होने के लिए कहा था।

आप जानते हैं कि विगत 34 वर्षों में वामफ्रंट सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में लगातार जोरदार आंदोलन किया गया था। सिर्फ प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा पुनः चालू करना ही नहीं, बल्कि अन्य बहुत सारी मांगों को लेकर आंदोलन करने के कारण हमारी पार्टी के 161 नेता-कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, कइयों को झूठे मामलों में आजीवन कारावास हुआ है। इसके बावजूद हमने कोई मांग नहीं उठायी कि वामफ्रंट सरकार का पतन हो, विधानसभा में भी उनके खिलाफ अनैतिक अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन नहीं किया, राज्यसभा चुनाव में भी बार-बार वामफ्रंट सरकार के प्रार्थियों को वोट दिए हैं। किन्तु नंदीग्राम-सिगूंर आंदोलनों का दमन करते हुए वामफ्रंट सरकार ने जिस तरह नृशंस तरीके से पुलिस और अपराधियों के द्वारा हत्या और बलात्कार कराया, तब हमने कहा, ये फासिस्ट हमला है। जनआंदोलनों का दमन करने के लिए कांग्रेस-बीजेपी सरकारों ने गोलियाँ चलायी, अनेकों की हत्या करवायी किन्तु सामूहिक बलात्कार नहीं करवाये। उनके शासन काल में सिर्फ दंगे के समय बलात्कार हुए हैं। नंदीग्राम में इस नृशंस आक्रमण के बाद ही पहली बार हमने मांग उठायी कि वामफ्रंट सरकार 'मस्ट गो' क्योंकि यह सरकार रहेगी तो आंदोलनों को दबाने के लिए और भी बेपरवाह होकर हमला करेगी। उस समय आम जनता भी वामफ्रंट सरकार का पतन चाहती थी। उसके बाद पिछली लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में। और हमने तो इस आंदोलन को बहुत मेहनत से मार खाकर गठित किया था। फलस्वरूप हमलोग थे आंदोलन की मूल शक्ति, साथ में तृणमूल थी और विपक्ष में वामफ्रंट सरकार थी। इसलिए हम तृणमूल के साथ वोट में एकजुट हुए थे। ये बात सभी राजनैतिक पार्टियाँ, प्रचार माध्यम, पुलिस प्रशासन सभी जानते हैं नंदीग्राम के आंदोलन में एसयूसीआई (सी) की वजह से प्रतिरोध संग्राम का गठन कर विजय प्राप्त करना संभव हुआ। नंदीग्राम और सिंगूर की जनता जानती है, किसने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। किन्तु बुर्जुआ प्रचार माध्यमों ने इस तरह प्रचार किया मानो तृणमूल ने ही सब कुछ किया हो, जिससे जनता हमारी भूमिका को नहीं जान पाए। इसी कारण इस बार चुनावी एकजुटता में जुड़कर हमारी भूमिका क्या थी ये जनता को बताने की जरूरत है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो कारण है वह है जनता की उस समय की जो मानसिकता थी, उससे हम समझ गये थे कि वामपफ्रंट हारेगा और तृणमूल जीतेगी। सीपीआई(एम) को दिखाकर तृणमूल पूरे चुनाव में मार्क्सवाद और वामपंथ के विरुद्ध प्रचार आंदोलन चलाएगी, उसे रोकने की जरूरत थी। तृणमूल को जरूरत थी हमारी पार्टी की साख को वोट में इस्तेमाल करने की, इसलिए वह हमारे साथ एकजुट थी। यह आप भी जानते हैं, सीपीआई(एम) के कार्यकर्ता भी जानते हैं तब भी पश्चिम बंगाल में प्रबल वामफ्रंट-विरोधी जनमत था, उससे रिगिंग के बिना, आतंक के बिना ही तृणमूल जीत जाती। नहीं तो वामफ्रंट के मुख्यमंत्री उनके अधीन प्रशासन के होने के बावजूद इतने वोटों से हार जाते! हम उनके साथ न होते तो तृणमूल व्यापक रूप से मार्क्सवाद और वामपंथ के विरुद्ध प्रचार कर जीतती, सिंगूर-नंदीग्राम के आंदोलन का श्रेय (क्रेडिट) भी वह ले जाती। वह भी हम वामपंथ और जनआंदोलन के स्वार्थ के लिए रोक सके।

हमारी शर्त थी, वामफ्रंट व सीपीआई(एम) की आलोचना करते हुए वे लोग मार्क्सवाद और वामपंथ पर आक्रमण नहीं करेंगे। तृणमूल ने वह मान लिया। फिर उनके साथ चुनावी एकता होने पर भी हमने कभी ये सब नहीं कहा कि तृणमूल 'जनतांत्रिक', 'प्रगतिशील', धर्मनिरपेक्ष है। बल्कि तृणमूल के साथ एक मंच पर उपस्थित होकर कहा कि तृणमूल सोचती है, वोट जीत कर सरकार बनाने के बाद सब कुछ कर देगी, किन्तु हम सोचते हैं, बार-बार सोचते हैं जनता की समस्या का समाधान सिर्फ क्रान्ति से ही होगा। तृणमूल सरकार भी पहले की कांग्रेस व वामफ्रंट सरकार की भांति शासन करेगी, जिस समय तृणमूल सरकार का गठन करेगी, उसी समय से हम सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। यह भी जान लें कि हमारी पार्टी ने ही सर्वप्रथम तृणमूल सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। तृणमूल के साथ जाने की हमारी तीन वजहें थी (1) नंदीग्राम-सिंगूर आंदोलन के तहत गठबंधन हुआ और उस आंदोलन की शुरूआत भी हमारी पार्टी ने ही की थी। (2) इसी आंदोलन से यह आहवान किया गया था कि वामफ्रंट सरकार का पतन सुनिश्चित हो। (3) चुनाव प्रचार में तृणमूल मार्क्सवाद व वामपंथ के विरुद्ध आक्रमण न कर सके। वामफ्रंट ने सरकार में रहते हुए 2006 में हमारी पार्टी को एकता का प्रस्ताव दिया था, किन्तु हम तैयार नहीं हुए, चूंकि वे वामपंथ के रास्ते से हट कर चल रहे थे। तृणमूल ने भी प्रस्ताव दिया था, हम राजी नहीं हुए। सीटों के लिए नहीं, मंत्री पद के लिए नहीं, हम एकता चाहते हैं जनहित में, जनआंदोलन के हित में, आदर्श व नीति-सिद्धांत पर।

आप यह भी जान लें कि गत विधानसभा चुनाव के पश्चात तृणमूल ने हमें मंत्री पद का ऑफर दिया था तो अगर हम उक्त अवसरों को स्वीकार करते तो लोकसभा चुनाव में जयनगर सीट हमें मिलती, परंतु हम उस पथ पर नहीं गये। यदि सिंगूर-नंदीग्राम आंदोलन नहीं होता तो हमारी पार्टी का तृणमूल के साथ एकबद्ध होने का सवाल ही नहीं उठता था। सीपीआई(एम) इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वोट की स्वार्थता के कारण, आंदोलन के स्वार्थ में नहीं और न ही आंदोलन के आधार पर। इसके अलावा यह भी जान लेना आवश्यक है कि कांग्रेस शुरूआत से ही बुर्जुआ वर्ग की विश्वसनीय पार्टी है, उसकी तुलना में तृणमूल भी क्षेत्रीय बुर्जुआ वर्ग का ही दल है जिसका स्थायित्व कितने दिन का है?

संवाददाता : तृणमूल ने तो चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। उसके उपरांत आपने उस समय गठबंधन नहीं छोड़ा, तब आप इस चुनाव में कांग्रेस के साथ जुड़ी सीपीएम के साथ क्यों नहीं?

प्रभाष घोष : हमने कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन का तीव्र विरोध किया था और कहा था कि हम एकबद्ध नहीं रहेंगे- यह बात भी हमने कही थी। उस समय जन भावना थी कि जैसे भी हो वामफ्रंट को हराना होगा। संवाददाताओं से जब प्रचार हुआ कि हमारी पार्टी इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी, उस समय नंदीग्राम-सिंगूर की आंदोलनकारी जनता, पश्चिम बंगाल के बहुत स्थानों की जनता का अनुरोध था कि हम इस गठबंधन से न निकलें। वे सभी बुद्धिजीवी जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनका भी यही अनुरोध मुखरित हो रहा था। इस स्थिति में हमने कहा कि हम सिर्फ तृणमूल के साथ जाएंगे—परंतु कांग्रेस के साथ नहीं। शुरूआत में तृणमूल का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं था, किन्तु दृढ़ता के साथ हम अपने सिद्धांत पर अटल रहे। तब तृणमूल को बाध्य होकर मानना पड़ा। जहाँ पर तृणमूल समर्थित कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े होंगे, वहाँ हम भी अपना उम्मीदवाद कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करेंगे। हमने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़े भी किए थे। उस समय प्रचार माध्यमों से यह खबर भी प्रसारित हुई थी। फलस्वरूप दोनों की तुलना करना सही नहीं है।

संवाददाता : प्रभाष बाबू, राष्ट्रीय स्तर पर छः पार्टियों का गठजोड़ है, क्या इसके बाद भी वह रहेगा?

प्रभाष घोष : हां, अवश्य। यह सब राष्ट्रीय स्तर पर है। दूसरे राज्यों में है और रहेगा।

संवाददाता : अगर ऐसा हो कि कांग्रेस आलाकमान बोले कि लेफ्टवालों के साथ हमारा किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है तो क्या सीपीआई(एम) के साथ गठबंधन करेंगे?

प्रभाष घोष : लेफ्टिस्ट यदि राजी होते हैं तो विचार-विमर्श करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा है कि दो जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में सीट समझौता किया जा सकता है। वह रहेगा।

संवाददाता : तब क्या आप वामपंथियों के विरुद्ध ही लड़ रहे हैं?

प्रभाष घोष : यह कहना ठीक नहीं होगा। हम भी तो वामपंथी हैं, तब हम वामपंथी रणनीति के विरुद्ध क्यों लड़ेंगे? बल्कि हम लड़ रहे हैं वामपंथ की मर्यादा की रक्षा के लिए। हम लड़ रहे हैं केन्द्र में सत्ता में बैठी बीजेपी, राज्य में सत्तासीन पार्टी तृणमूल, राष्ट्रीय बुर्जुआ दल कांग्रेस के विरुद्ध एवं सीपीआई(एम) सहित वामफ्रंट के अन्य दल जो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सुविधावादी राजनीति कर रहे है उसके विरुद्ध। ●

जमीन छीनने की नीति के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन

सोनीपत : ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन की जिला कमेटी ने 11 अप्रैल को हरियाणा सरकार की जमीन खोसू नीति का कड़ा विरोध किया। सामलात भूमि व पंचायती भूमि से गांव की जनता को बेदखल करने के कदम के खिलाफ सोनीपत जिला मुख्यालय पर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कृषक खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 मार्च को पंजाब जोत अधिनियम 1948 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देकर हरियाणा के सभी गांवों की सामलात भूमि व पंचायत भूमि से बेदखल कर दिया है। हरियाणा सरकार इस सामलात व पंचायती भूमि को अपने कब्जे में लेकर अपने भूमि बैंक में डाल कर देशी-विदेशी पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी में लगी हुई है। जमीन चाहे मुस्तर्क मालिकाने की हो, चारागाह व गोरा हो, सरकार इन सभी की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है जो जमीन कृषि लायक है जिसे पूरे गांव की मौजूदगी में हर साल बोली पर उठाया जाता है, चाहे ऐसी जमीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या बैकवर्ड क्लास के परिवारों के लिए आरक्षित भी क्यों न हो, इन सभी जमीनों को अपने कब्जे में लेकर पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी में खटटर सरकार लगी हुई है। हर गांव में ऐसी जमीनें हैं जिनसे ग्रामीणों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। इन जमीनों से होने वाली आमदनी को गांव के विकास कार्य में खर्च किया जाता है। हरियाणा सरकार सब कुछ तहस-नहस करने जा रही है। अभी प्रदेश की जनता को यह बात मालूम नहीं है। अन्य चुनावी पार्टियों ने भी इसके विरोध में आकर मुंह नहीं खोला है। शमशेर सिंह ने कहा कि अगर 1 मई तक सरकार ने यह कदम वापस नहीं लिया तो केकेएमएस हरियाणा में जनजागरण अभियान चलायेगा। केकेएमएस के अलावा अन्य किसान संगठन भी इससे पहले जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे हुए थे। उनके नेताओं ने भी केकेएमएस के आन्दोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। संगठन के जिला सचिव जयकरण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर ज्ञापन भी दिया गया।

ऐतिहासिक मई दिवस

(पृष्ठ 1 का शेष)

विश्व सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन के महान् नेता, शिक्षक व पथ-प्रदर्शक फ्रेडरिक एंगेल्स के आह्वान पर 1890 से पहली मई का दिन सारी दुनिया में मजदूर-दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मई दिवस का महत्व दर्शाते हुए उन्होंने कहा था कि, ''एक तरफ दुनियाभर के सर्वहारा-मजदूरों का खेमा है जो सर्वत्र मुक्ति के परचम तले जीत की तरफ लम्बे डग भर रहा है, दूसरी तरफ अपनी शोषणमूलक सुविधाओं-विशेषाधिकारों को बचाने के लिए पूंजीपतियों, धनवानों व प्रतिक्रियावादियों ने हाथ मिला लिये हैं। इन दोनों खेमों के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है...जीत आपकी होगी–आगे बढ़ो।'' इतिहास गवाह है कि तमाम दमन-उत्पीड़न के बावजूद मजदूर आन्दोलन आगे बढ़ा और भारत समेत हर देश में 8 घण्टे के कार्य दिवस को कानूनी मान्यता मिली। याद रहे, मजदूर-कर्मचारियों के हक में जितने भी कानून बने हैं वे सभी हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों के फल हैं।

सभी समस्याओं की जड़ है पूंजीवाद

मालिक और मजदूर इन दो वर्गों में विभाजित समाज में इन दोनों वर्गों के हित न केवल अलग-अलग हैं बल्कि एक-दूसरे के विपरीत भी हैं। मजदूर अपनी श्रमशक्ति बेचता है और मालिक पूंजीपति इसे खरीदता है। मजदूरों का खून चूस कर पूंजीपति अपने मुनाफे के अम्बार लगाते जाते हैं। इस निर्मम लूट के चलते मेहनतकश जनता की खरीद शक्ति घटती जाने से बाजार घटता जा रहा है। आज विश्व पैमाने पर पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था बाजार के संकट में फंस गई है और इसके संकट का सारा बोझ मजदूर-कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकशों पर डाला जा रहा है। पूंजीवादी शोषण के चलते अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब। इस मरणासन्न विश्व-पूंजीवाद का अभिन्न अंग होने के चलते हमारे देश में पूंजीवाद संकटग्रस्त है। यहां भी लोगों की दशा कोई बेहतर नहीं है। शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था को आर्थिक मंदी के संकट से उबारने के लिए 1991 में लाया गया पूंजीवादी भूमण्डलीकरण-निजीकरण का नुस्खा भी काम नहीं आया। इन नीतियों के चलते महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शिक्षा व इलाज बेहद महंगा होता जा रहा है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक समस्याएं घनघोर हो उठी हैं। मजदूर-कर्मचारियों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सेवा क्षेत्र का निजीकरण-व्यापारीकरण किया जा रहा है। अंशदान के रूप में वेतन से पैसे काटकर पेन्शन देने की स्कीम शुरू की गई है। स्थायी कामों में भी ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नियुक्त श्रमशक्ति का 68 फीसद कैज्यूअल यानी या अस्थाई कर्मचारी हैं जिनसे कम तनख्वाह पर काम लिया जाता है और नियमित या पक्का नहीं किया जाता है। इन्हें मालिक मनमर्जी से जब चाहे हटा देते हैं। दिहाड़ी मार लेते हैं। इन्हें घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता है। कच्चे कर्मचारियों व स्कीम वर्करों को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता और ग्रामीण चौकीदार सरकारी काम करते हैं फिर भी सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। भले ही यहाँ 8 घण्टे के कार्य दिवस को कानूनी मान्यता मिल चुकी है लेकिन देश-प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों व कारखानों में 8 घण्टे का कार्य-दिवस, न्यूनतम वेतन, वेज स्लिप, हाजरी कार्ड, हाजरी रजिस्टर, ई.एस.आई. व पी.एफ. ग्रेच्युटी, पेन्शन जैसे अनिवार्य कानूनी प्रावधान लागू नहीं हैं। जाहिर है के 1886 में मजदूरों का जितना शोषण किया जाता था आज उससे कहीं ज्यादा शोषण है। मजदूरों की हालत बन्धुआ गुलामों से भी बदतर है। भवन निर्माण कारीगर-मजदूर-मिस्त्रियों के कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने व हितलाभ पाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। सारी बेजा शर्तें थोंपी हुई हैं। इसलिए बहुत से श्रमिक पंजीकृत ही नहीं हैं। वे बोर्ड से मिलने वाले हितलाभों से वंचित हैं। श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने देशी-विदेशी कारपोरेट घरानों की इच्छानुसार औद्योगिक विवाद एक्ट, फेक्ट्री एक्ट, ठेका श्रमिक एक्ट व वेतन भुगतान कानून में घोर मजदूर-विरोधी संशोधन किये हैं। यूनियन बनाने व हड़ताल करने के बड़े संघर्षों से हासिल किये गये जनतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। सरकार की इन सब मजदूर-विरोधी नीतियों व कदमों के खिलाफ 11 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से साझा मजदूर आन्दोलन जारी है। आगामी 2 सितम्बर 2016 को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाना है।

मुक्ति का रास्ता

इन असहनीय और दमघोंटू हालात के खिलाफ जोरदार मजदूर आन्दोलन खड़ा करना ही बचने का एकमात्र रास्ता है। लोग अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल भी हुई। लेकिन इस युग के महान मार्क्सवादी चिंतक सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने यह सीख दी है कि सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के बिना महज स्वत:स्फूर्त विक्षोभ फूट पड़ने से ही समाज में क्रांतिकारी बदलाव नहीं आता है बल्कि उल्टे लोगों में निराशा-हताशा और राजनैतिक उदासीनता छा जाती है। समस्याओं से परेशान हो कर जब जनता में आन्दोलन की चाह पैदा होती है तो जनता में फूट डाल दी जाती है। हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-सिख, हरियाणवी-बिहारी, गुजराती-मराठी का झगड़ा करा दिया जाता है। यह पूंजीपतियों की एक खतरनाक चाल है। याद रखें, मजदूर कहीं का भी हो, कोई भी हो, उन सब का हित एक ह। वे आपस में कभी नहीं लड़ते। इसीलिए हमारा नारा है : दुनिया के मजदूरो, एक हो!! मजदूर एकता व संगठन को मजबूत करते हुए, मजदूर आन्दोलन-जनान्दोलन करते हुए, जनकमेटियों-यूनियनों का निर्माण करते हुए जनता की राजनैतिक शक्ति को जन्म देते हुए जब राजसत्ता लोगों के हाथों में आएगी तब सही मायने में मुक्ति मिलेगी। मजदूर क्रान्ति के जरिये पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर शोषणहीन समाज कायम करना ही मजदूर आन्दोलन का ध्येय है। साम्यवाद केवल मजदूरों का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का सवाल है, मुक्ति का रास्ता है। मजदूर-कर्मचारी आन्दोलन को स्तर दर स्तर पूंजीवाद-विरोधी दिशा में आगे बढ़ाने के लिये जरूरी है कि पूंजीपतियों की ताबेदार उन तमाम धोखेबाज पार्टियों, नेताओं व संगठनों का पर्दाफाश किया जाए जो एक तरफ तो सत्ता में रहने के लिए पूंजीपतियों के स्वार्थ में जनविरोधी, मजदूर-विरोधी व दमनकारी नीतियों को लागू करते हैं और दूसरी तरफ उनके खिलाफ आन्दोलन करने का दिखावा करते हैं। मई दिवस का साफ संदेश है कि इन संशोधनवादी विश्वासघातियों को मजदूर आन्दोलन से अलग-थलग करें। हर तरह के शोषण-उत्पीड़न से पूर्ण मुक्ति पाने के अपने ऐतिहासिक लक्ष्य की ओर लाल परचम फहराते हुए लगाातार आगे बढ़ें। शोसक पूंजीपति वर्ग को परास्त करने की यह पूर्वशर्त है। मई दिवस आज हमें आन्दोलन की नई लहर खड़ी करने के लिए ललकार रहा है। आइये, इसका हम दृढ़ संकल्प लें! ●

1 लाख सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी के खिलाफ रोष प्रदर्शन

भोपाल (म.प्र.) : म.प्र. के 1 लाख 8 हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी के खिलाफ 7 अप्रैल को छात्र संगठन एआईडीएसओ ने स्थानीय नीलम पार्क में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया। भोपाल, ग्वालियर, गुना, शोकनगर, सागर आदि जिलों से सैकड़ों छात्र इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए।

विरोध सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मुदित भटनागर ने कहा कि गत वर्ष भी सरकार ने पीपीपी मॉडल के नाम पर स्कूलों का निजीकरण करने की कोशिश की थी। लोगों के जबरदस्त विरोध के चलते शासन को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा था। अब फिर सरकार गुप-चुप तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। यह शिक्षा-विरोधी कदम है। इससे शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे बहुत सारे छात्र शिक्षा से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने इसको रोकने के लिए जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करने की छात्रों से पुरजोर अपील की। उन्होंने स्थायी आधार पर कुशल अध्यापक भर्ती करने, 8वीं तक बेरोकटोक पास करना बंद करने और मूलभूत अधिसंरचनात्मक ढांचा बढ़ाने के लिए शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग की।

सभा को संगठन के म.प्र. राज्य कार्यालय सचिव विनोद लोगरिया, सचिवमण्डल सदस्य अजीत सिंह, बबीता समर, श्रुति शिवहरे, पारूल शर्मा व निवेदिता खातरकर ने भी सम्बोधित किया। सभा का संचालन संगठन के राज्य सचिव सचिन जैन ने किया। अंत में हजारों की संख्या में संग्रह किये गये हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया।

जिला पार्टी सेण्टर के नये भवन का उद्घाटन

पार्टी सेण्टर का उद्घाटन करते हुए कॉ. सी.के. लुकोस

पलक्कड 3 अप्रैल को एसयूसीआई(सी) केन्द्रीय कमेटी सदस्य व केरल राज्य सचिव कॉमरेड सी.के. लुकोस ने पलक्कड जिला पार्टी सेण्टर के नये भवन का उद्घाटन किया। पार्टी के साथियों, समर्थकों-हमदर्दों के चंदे से जमीन खरीदी गई और निर्माण किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पार्टी के केरल राज्य सचिवमण्डल सदस्य कॉ. जी.एस. पदमकुमार ने की। पलक्कड जिला कमेटी सचिव कॉमरेड के. अब्दुल अजीज ने समारोह में आये लोगों का स्वागत किया। पार्टी की तमिलनाडु राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. रंगास्वामी ने भी बात रखी। देशीय कृषक संगठन के नेता श्री रामकृष्णन और हमारी पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कॉ. आर. राजेश ने आभार व्यक्त किया।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C).
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com
फोन नं. : 011-25726631, 9868350503